सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार
" भलाई करते रहिए, बहते हुए पानी की तरह
बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह...!! "
अज्ञात...

वर्ष-01 अंक-147 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, मंगलवार 16 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए

महंगी हुई बिजली : 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोत्तरी, आयोग ने कहा- अन्य राज्यों से सस्ती

400 यूनिट तक खपत पर एम-ऊर्जा से मिलती रहेगी आधे दर पर बिजली

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2026-27 के लिए नई विद्युत दरें घोषित कर दी हैं। नया टैरिफ 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। घोषित दरों में पिछले वर्ष की तुलना में औसतन 6.23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रभाव

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीमसिंह कंवर ने बताया कि घरेलू श्रेणी में औसतन 30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है।
- 0 से 100 यूनिटः 30 पैसा प्रति यूनिट
- 101 से 200 यूनिटः 30 पैसा प्रति यूनिट
- 201 से 400 यूनिटः 40 पैसा प्रति यूनिट
- 401 से 600 यूनिटः 40 पैसा प्रति यूनिट
- 601 से अधिकः 50 पैसा प्रति यूनिट

एम-ऊर्जा से राहत बरकरार

मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट की खपत पर हाफ बिजली बिल का लाभ मिलता रहेगा। इस कारण इस श्रेणी में औसतन 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट की ही वृद्धि होगी।

किसानों पर नहीं पड़ेगा असर

कृषि पंपों की बिजली दरों में 40 पैसे की वृद्धि हुई है, लेकिन इसका भार राज्य शासन वहन करेगा। किसानों पर वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्योग और व्यवसायिक दरें

गैर-घरेलू श्रेणी में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की

वृद्धि की गई है। उच्चदाब स्टील उपभोक्ताओं में 220 केव्ही और 132 केव्ही पर 30 पैसे प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार और डिमांड चार्ज में 25 रुपये प्रति केव्हीए की वृद्धि की गई है। 33 केव्ही पर 40 पैसे और 11 केव्ही पर 30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है।

विशेष छूट

1. बस्तर-सरगुजा के हॉस्टल :

आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित शासकीय और निजी विद्यार्थी हॉस्टल को व्यवसायिक से घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया।

2. विलंब अधिभार में कमीः पहले 1.5 प्रतिशत प्रति माह लगता था, अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन लगेगा।

3. ऑफ पीक छूटः 10 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खपत पर 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट।

पीएम सूर्यघर से बिल शून्य संभव

घरेलू उपभोक्ता पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर खपत 400 यूनिट के भीतर सीमित कर सकते हैं। कई उपभोक्ताओं का बिल शून्य भी हो रहा है। प्रबंध निदेशक के अनुसार, वृद्धि के बाद भी छत्तीसगढ़ की दरें झारखंड, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से कम हैं।

छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय रैपर एपी राजा उर्फ चेतन का निधन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय रैपर चेतन चांडक उर्फ एप्पी राजा का रायपुर स्थित अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर सामने आते ही संगीत जगत, प्रशंसकों और कलाकारों के बीच शोक की लहर दौड़ गई।

एप्पी राजा का जीवन संघर्ष और मेहनत की एक ऐसी कहानी है, जिसमें कठिन परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया और रैप म्यूजिक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जन्म वर्ष 1994 में नवागढ़ में हुआ था। उनके माता-पिता मूल रूप से राजस्थान के जैसलमेर जिले के रहने वाले थे, जो बाद में रोजगार और जीवनयापन के कारण छत्तीसगढ़ के बेमेतरा और फिर नवागढ़ में आकर बस गए।

एप्पी राजा ने अपने बचपन के शुरुआती वर्ष दुर्ग में बिताए, जहां से उनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ष 2002 के आसपास उनका परिवार भानुप्रतापपुर (कांकेर) में जाकर बस गया। यहां उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा और रोजाना भानुप्रतापपुर से कांकेर तक यात्रा करके शिक्षा प्राप्त करते थे। कांकेर के एक निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही एप्पी राजा ने रचनात्मकता की दिशा में कदम बढ़ाया। कक्षा 7वीं में उन्होंने अपना पहला रैप लिखा, जिसने उनके संगीत के प्रति झुकाव को दर्शाया। समय के साथ उनका रुझान रैप और म्यूजिक की ओर बढ़ता गया।

हालांकि जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। 11वीं कक्षा के दौरान उनके पिता को हार्ट अटैक आया, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई। इस कठिन समय में परिवार की जिम्मेदारी बढ़ने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने रोजगार की तलाश में गुजरात के सूरत का रुख किया, जहां उन्होंने काम किया ताकि परिवार को आर्थिक सहयोग मिल सके। कुछ समय बाद वे भिलाई लौटे और वहां मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब में भी काम किया, जहां उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

पंजाब में रहते हुए एप्पी राजा की मुलाकात एक म्यूजिक डायरेक्टर से हुई, जिसने उनके टैलेंट को पहचान दी। यहीं से उन्हें स्टूडियो में काम करने का मौका मिला और उन्होंने गानों पर काम करना शुरू किया। यह उनके करियर का वह दौर था, जिसने उन्हें संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता दिया। धीरे-धीरे एप्पी राजा ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रैप म्यूजिक की शुरुआत की। उन्होंने अपने गानों को यूट्यूब पर रिलीज करना शुरू किया, जहां उन्हें लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। उनकी शैली, भाषा और स्थानीय जुड़ाव ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। आज एप्पी राजा छत्तीसगढ़ी रैप म्यूजिक के उभरते हुए नामों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाई है। उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि अगर इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी सफलता हासिल की जा सकती है।

बीएसपी से 250 टन लोहा चोरी का मास्टर माइंड हिरासत में, यूपी से भिलाई लाया गया

17 जून को पुलिस करेगी मामले का खुलासा, बेटा अब भी फरार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र से 250 टन लोहा चोरी मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी और इनामी बदमाश संजय सिंह को दुर्ग पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश से हिरासत में लेकर भिलाई लाया जा रहा है। पुलिस 17 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेगी।

10 हजार का इनामी था संजय सिंह

पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय सिंह पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इस मामले में संजय सिंह का बेटा अभय सिंह भी सह-आरोपी है जो अभी फरार है। अभय की गिरफ्तारी पर भी पुलिस ने 10 हजार का इनाम रखा है। उसकी तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं।

10 बैंकों के खाते सीज, मनी-ट्रेल पर जांच

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डीआईजी व दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के नेतृत्व में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से 10 अलग-अलग बैंकों की पासबुक

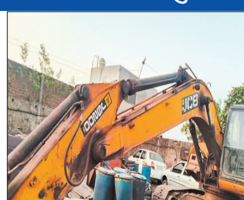

और चेकबुक जब्त कर सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच एजेंसियां अब इस संगठित अपराध के मनी-ट्रेल पर काम कर रही हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि चोरी से हुई काली कमाई का बंटवारा कैसे होता था और बीएसपी के अंदर-बाहर इसमें कौन शामिल था।

ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी जांच के घेरे में

सूत्रों के अनुसार 250 टन लोहे और स्क्रैप के परिवहन में शहर के कुछ ट्रांसपोर्टर नेटवर्क के शामिल होने की आशंका है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है।

फिलहाल दुर्ग पुलिस ने आरोपी संजय सिंह को हिरासत में लिया है। कल 17 जून को पुलिस पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक करेगी।

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जल्द लागू होगा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आश्वासन

राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में दिया भरोसा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों ने 14 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में लंबे समय से लंबित अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने की मांग प्रमुखता से रखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मांग पर गंभीरता दिखाते हुए अधिनियम लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है।

बैठक में परिषद के अध्यक्ष रविन्द्र पराशर, अनुशासन समिति के अध्यक्ष प्रशांत प्रभात तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ताओं से जुड़े अन्य मुद्दों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन का स्वागत करते हुए इसे अधिवक्ता समुदाय के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया।

हाईकोर्ट के आदेश पर भिलाई में बड़ी कार्रवाई, अवैध मदरसा, मकान और दुकानें ध्वस्त

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देश पर भिलाई नगर निगम ने जोन-01 नेहरू नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडब्ल्यूएस की जमीन पर बने अवैध मदरसा, मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। निगम की टीम ने उल्लास नगर एवं नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवा पब्लिक स्कूल के सामने ईडब्ल्यूएस की जमीन पर लंबे समय से बने अवैध मदरसा और आवासीय मकानों को हटाया। यह भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र

हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिए स्वीकृत थी, लेकिन इस पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था।

इसी क्रम में नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदूलाल चंद्राकार हॉस्पिटल के बाजू में बने अतिक्रमण वाले दुकानों एवं आवासों पर भी कार्रवाई की गई। निगम ने बताया कि कार्रवाई से पहले अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे।

हाईकोर्ट के आदेश के पालन में जिला प्रशासन, निगम प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय दंडाधिकारी दशरथ सिंह राजपूत, शहर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, तहसीलदार डीकेश्वर साहू, उपायुक्त सह जोन आयुक्त दिनेश कोसरिया, जोन आयुक्त येशा लहरे, कुलदीप गुप्ता, अमरनाथ दुबे, अजय गौर, कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, संजय वर्मा, अरविन्द शर्मा समेत सहायक राजस्व अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और बेदखली दल के सदस्य मौजूद रहे। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अवैध संरचना तत्काल खाली करें, अन्यथा कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

शौर्य चक्र विजेता दो पुलिस निरीक्षकों का दुर्ग में नागरिक अभिनंदन

नक्सल मोर्चे पर अदम्य साहस दिखाने वाले लक्ष्मण केवट और रामेश्वर देशमुख सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

पुलिस लाइन सभागार में रविवार को शौर्य चक्र से सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख का नागरिक अभिनंदन किया गया। नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय साहस और नेतृत्व के लिए दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

एसपी ने बताया प्रेरणास्रोत

पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि शौर्य चक्र जैसा राष्ट्रीय सम्मान पाना गौरव की बात है। दोनों अधिकारियों ने विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है। उनकी उपलब्धियां पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गर्व का विषय हैं। उन्होंने युवा पुलिसकर्मियों से जनता की सुरक्षा और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

58 नक्सलियों के शव बरामद : रामेश्वर देशमुख

निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख 18 जून 2007 को दंतेवाड़ा में आरक्षक बने। जुलाई 2015 में निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए। बीजापुर, राजनांदगांव और कांकेर में सेवाएं दीं। वर्तमान में थाना प्रभारी भानुप्रतापपुर हैं। 25 सफल मुठभेड़ों में शामिल रहे और 58 नक्सलियों के शव बरामद करने में योगदान दिया। इन्हें एक शौर्य चक्र, 2 पुलिस वीरता पदक, एक केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक और आउट ऑफ टर्न पदोन्नति मिली है।

40 मुठभेड़ों में रहे शामिल : लक्ष्मण केवट

निरीक्षक लक्ष्मण केवट 12 अप्रैल 2007 को सूरजपुर में आरक्षक के पद पर भर्ती हुए। नवंबर 2014 में निरीक्षक बने। बीजापुर, राजनांदगांव और कांकेर में सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में थाना प्रभारी पखांजूर हैं। नक्सल विरोधी अभियानों में 40 सफल मुठभेड़ों में शामिल रहे और 97 नक्सलियों के शव बरामद करने में भूमिका निभाई। उन्हें एक शौर्य चक्र, 6 पुलिस वीरता पदक, एक केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक और आउट ऑफ टर्न पदोन्नति मिल चुकी है।

शौर्य चक्र का महत्व

शौर्य चक्र शांति काल का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह असाधारण साहस, वीरता और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में पराक्रम दिखाने वाले सैन्य, अर्धसैनिक, पुलिस अधिकारियों और नागरिकों को दिया जाता है। समारोह में एएसपी शहर, एएसपी ग्रामीण, सीएसपी, पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, प्रबुद्ध नागरिक और पुलिस परिवार के सदस्य मौजूद रहे। उपस्थितजनों ने दोनों अधिकारियों के संघर्षपूर्ण सेवाकाल के अनुभव सुने।

महापौर निधि के कार्यों की हुई समीक्षा, अधिकारियों से मांगी गई प्रगति रिपोर्ट

फील्ड में रहकर कार्यों की निगरानी करें अधिकारी, निर्माण सामग्री की जांच के दिए निर्देश, विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा से कोई समझौता नहीं : महापौर अलका बाघमार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग की महापौर अलका बाघमार की अध्यक्षता में महापौर कक्ष में शहर में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम क्षेत्र में चल रहे एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान 15वें वित्त आयोग एवं महापौर निधि के अंतर्गत संचालित कार्यों के साथ सड़क डामरीकरण, सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण, नाली-पुलिया निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लॉक, पेयजल व्यवस्था तथा शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

महापौर अलका बाघमार ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा स्पष्ट किया कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा एवं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं। उन्होंने महापौर निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए जानकारी ली कि एक वर्ष में प्राप्त 1 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि से

कितने कार्य पूर्ण हुए हैं तथा कितने कार्य प्रगतिरत अथवा लंबित हैं। साथ ही पुराने और नवीन स्वीकृत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित ठेकेदारों को समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं फील्ड में उपस्थित रहकर निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें ताकि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बैठक में भूमिपूजन के उपरांत संबंधित स्थलों पर शिलापट्ट स्थापित करने तथा कार्यों की प्रगति का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड संधारित कर नियमित जानकारी साझा करने के निर्देश भी दिए गए। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि, शहर के विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य करें।

लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने कहा कि नगर निगम द्वारा संचालित विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है तथा जनहित के सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कर नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, शेखर चन्द्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकर, कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, सहायक अभियंता संजय ठाकुर, हरिशंकर साहू, पंकज साहू, विनोद मांझी, अपर्णा मिश्रा सहित निगम के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

खास खबर

अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी दुर्ग की नई टीम घोषित, सैय्यद आसिफ अली बने अध्यक्ष, जाकिर खोखर को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शहर की प्रमुख सामाजिक एवं जनकल्याणकारी संस्था अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी, दुर्ग (छत्तीसगढ़) ने संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं जनसेवा के लिए समर्पित बनाने के उद्देश्य से अपनी नई कायर्कारिणी, सरपरस्त मंडल, जरे निगरान एवं सदस्यों की सूची जारी कर दी है। नई टीम के गठन के साथ संगठन ने समाज सेवा, शिक्षा के प्रसार, आपसी भाईचारे, धार्मिक सौहार्द और जनकल्याण के कार्यों को नई गति देने का संकल्प व्यक्त किया है।

नई कार्यकारिणी में सैय्यद आसिफ अली को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि जाकिर खोबर को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपाध्यक्ष पद पर मासूब अली, तबरेज खान एवं अजमल अली को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जुनेद लाल आजमी और जुबेर खान को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। सचिव पद पर फैजान अशरफ, शेख वसीम (विक्की) एवं इकबाल कुरेशी को नियुक्त किया गया है। संगठन के प्रवक्ता के रूप में सैय्यद अनीस अली तथा मीडिया प्रभारी के रूप में सैय्यद सैफ जिम्मेदारी संभालेंगे।

अनुभवी सरपरस्त मंडल और निगरानी समिति का गठन : संगठन ने मार्गदर्शन और संगठनात्मक मजबूती के लिए वरिष्ठ एवं अनुभवी लोगों को सरपरस्त मंडल में शामिल किया है। इसके अलावा जरे निगरान (निगरानी समिति) का भी गठन किया गया है, जो संगठन की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

समाजहित के कार्यों को मिलेगी नई दिशा : कमेटी पदाधिकारियों ने कहा कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी शहर दुर्ग वर्षों से सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और मानवीय सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा के प्रचार-प्रसार, सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य किया जाएगा।

सभी समाजजनों से सहयोग की अपील : कमेटी की ओर से समाजजनों से संगठन के कार्यों में सहयोग, सहभागिता और मार्गदर्शन देने की अपील की गई है, ताकि समाज के विकास, शिक्षा के विस्तार और सामाजिक सौहार्द को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

मीडिया प्रभारी सैय्यद सैफ ने बताया कि संगठन का उद्देश्य केवल एक समुदाय तक सीमित न होकर समाज में सद्भाव, शिक्षा और मानवता की सेवा को बढ़ावा देना है। नई टीम इसी सोच के साथ कार्य करेगी और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देगी। नई कार्यकारिणी के गठन पर समाज के विभिन्न वर्गों ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं।

जन समर्पण सेवा संस्था ने जरूरतमंदों को कराया भोजन, वितरित की आवश्यक सामग्री

दुर्ग। अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) की अमावस्या के अवसर पर जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा जरूरतमंदों, वृद्धजनों एवं असहाय लोगों के लिए विशेष सेवा अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान भोजन वितरण के साथ दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री भी प्रदान की गई। संस्था के अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा बंटी ने बताया कि जन समर्पण सेवा संस्था पिछले 9 वर्ष 6 माह (3450 दिनों) से लगातार बिना रुके दुर्ग रेलवे स्टेशन एवं शहर के विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से निवासरत मजदूरों, असहायों, महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांगजनों को प्रतिदिन रात्रि में निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही संस्था के सदस्य विभिन्न पर्व एवं विशेष अवसरों पर जरूरतमंदों की सहायता करते आ रहे हैं।

अधिकमास अमावस्या के अवसर पर 14 जून की शाम संस्था के सदस्यों ने पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम तथा कादंबरी नगर स्थित महिला अनाथ एवं वृद्ध आश्रम पहुंचकर सेवा कार्य किया। यहां सभी वृद्धजनों को भोजन के लिए नई स्टील की थाली, गिलास एवं चम्मच वितरित किए गए तथा भोजन कराया गया। भोजन उपरांत वृद्ध पुरुषों को लुंगी, महिलाओं को नाइटी तथा सभी को मिष्ठान, नमकीन, फल, बिस्किट, साबुन, निरमा, तेल, पेस्ट, कंघी सहित अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। इसके पश्चात संस्था के सदस्यों ने दुर्ग रेलवे स्टेशन एवं शहर के विभिन्न फुटपाथों पर निवासरत जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन एवं दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराई।

परमात्म ज्ञान सुनने का अर्थ है उसको आचरण में लाना, हर दिन देखना कि मेरे में दिव्यता कितनी आई है : हेमलता

ब्रह्माकुमारीज "आनंद सरोवर" बघेरा में आध्यात्मिक समागम

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के बघेरा स्थित "आनंद सरोवर" में छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय निर्देशिका ब्रह्माकुमारी हेमलता दीदी का शुभागमन हुआ 'उनके सानिध्य में सभी भाई बहनों के आध्यात्मिक उन्नति लिए सुंदर आध्यात्मिक समागम हुआ 'ब्रह्माकुमारी दुर्ग की संचालिका रीटा दीदी ने हेमलता दीदी के स्वागत में कहा कि आपके निर्देशन में सभी स्थान के भाई-बहनों को समय प्रति समय आपके अनुभव युक्त मार्गदर्शन मिलते रहते हैं । आप अपनी तपस्या व कुशाग्र बुद्धि के बल से मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ (इन्दौर जोन) को ब्रह्माकुमारीज के इतने सेवाकेन्द्रों में अनेक बातों पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलायी, यह आपके कुशल नेतृत्व की ही प्रमाण है। इस अवसर पर कुमारी तेजस्वी,प्रियांशी,युक्ति, चंद्राणी द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया ।

उल्लेखनीय है कि जून मास को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के प्रथम मुख्य संचालिका ओम राधे (मम्मा) के पुण्य स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है ।इस मास में विशेष आध्यात्मिक उन्नति के लिए आंतरिक तपस्या के भिन्न-भिन्न आयोजन किए जाते हैं ।इसी श्रृंखला में हेमलता दीदी ने आध्यात्मिक पुरुषार्थ की छोटी-छोटी बातों पर अपना उदबोधन दिया । उन्होंने कहा छोटी-मोटी कमियां किसी की देखने से हमारे अंदर उसके प्रति भाव बदल जाता है, भावना बदल जाती है और जब भाव बदला, भावना बदली पहले क्या बदलेंगी, दृष्टि बदलेगी। पहले हमारा किसी के साथ बहुत अच्छा संबंध था लेकिन किसी ने उसके बारे में मेरे को कोई छोटी सी नेगेटिव बात बता दिया आप उससे इतना अच्छा संबंध रखते हो वह तो आपके लिए ऐसा बोलते हैं अब हमने यह भी नहीं जानने की कोशिश की सचमुच में भी उसने ऐसा बोला भी है या कि नहीं ।

जिसके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है और कोई उसके लिए आकर ऐसा बोल दे तो उसके प्रति आपकी दृष्टि बदल जाती है या नहीं ? वही व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसे शंका की दृष्टि से देखते हो उसकी हर एक्ट पर आप वही जो आपको बोला गया है आप उसे उसी नजरिया से देखने की कोशिश करते हैं तो आप सोचो छोटी सी नेगेटिव बात ने मेरी दृष्टि को मेरे दृष्टिकोण को मेरे व्यवहार को कितना बदल दिया। पहले जिससे जितना प्यार से सम्मान से बात करते थे अब करेंगे ? क्यों नहीं करेंगे ?छोटी सी तो नेगेटिव बात थी, लेकिन वह नेगेटिव बात ने मेरे मन को भी उसके प्रति नेगेटिव बना दिया तो हर चीज नेगेटिव हो जाती है भले वह है नहीं ' इसलिए सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करो।'

अभी आंतरिक तपस्या हम कर रहे हैं स्वयं को इतना शांत बना सकते हैं कि कोई कुछ भी उल्टा करें मेरा मन हलचल में नहीं आएगा 'मेरे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे मेरा मन हर परिस्थिति में कोई भी बात आए तो भी एकदम शांत रहेगा क्योंकि मेरा स्वधर्म ही शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांति है इसे महसूस कर स्वयं को परिवर्तन करना है।' काव्यमय मंच संचालन में ब्रह्माकुमारीज में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली रूपाली दीदी ने हेमलता दीदी के साथ के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि आज ब्रह्माकुमारीज का भिन्न-भिन्न स्थानों में इतना व्यापक विस्तार हो रहा है । दीदी के निर्देशन में ही रायपुर स्थित ब्रह्माकुमारीज के "शांति शिखर" के उद्घाटन में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ । यह सब दीदी के दृढ़ इच्छा शक्ति व तपस्या का फल है।

विकसित भारत जी-राम-जी अंतर्गत संभाग स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

विकसित भारत जी-राम-जी अंतर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 15 एवं 16 जून 2026 को किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य विकसित भारत के संकल्पों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता संवर्धन करना, कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की जानकारी प्रदान करना तथा ग्राम स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना है।

इस प्रशिक्षण में दुर्ग संभाग के दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला पंचायत के अधिकारी-कमर्चारी सहभागी हैं। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर एवं सहायक परियोजना अधिकारी (मनरेगा) द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना के प्रमुख उद्देश्यों एवं घटकों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं भविष्य के लिए तैयार बनाना है। योजना के अंतर्गत स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा सतत विकास हेतु उत्पादक आधारभूत संरचना विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय आवश्यकताओं एवं आर्थिक क्षमता के अनुरूप आजीविका उन्मुख आधारभूत संरचना के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने बताया कि विकसित ग्राम पंचायत योजना का तीसरा महत्वपूर्ण आयाम "भविष्य के लिए तैयार ग्राम पंचायतें" है, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी, सतत विकास, जलवायु अनुकूलन एवं नवाचार को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शामिल कर विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण परिवर्तन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को ग्राम स्तरीय योजना निर्माण, संसाधनों के प्रभावी उपयोग, अभिसरण आधारित विकास कार्यो तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने विकसित ग्राम पंचायत योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए ग्राम पंचायतों को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी बी-ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ शपथ ग्रहण समारोह

सांसद विजय बघेल ने दिलाई नई कार्यकारिणी को शपथ

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

बी-ब्लॉक, तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं अनुशासन की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में विधायक एवं पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष ललित चंद्राकर विशिष्ट अतिथि रहे। वार्ड पार्षद श्रीमती सविता धवस भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुई। अध्यक्ष सुनील चौरसिया और पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कॉलोनी के विकास, स्वच्छता, सुरक्षा और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई टीम कॉलोनीवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी।

नई कार्यकारिणी में ये शामिल

अध्यक्ष सुनील चौरसिया, महासचिव आरके दत्ता, लक्षप्रद, जितेंद्र, श्रीमती पायल सिंह पवार, श्याम लाल देवांगन, केएन दिवाकर, काशीराम देशमुख, भीमराव फुसे, आईएम वाम्हने, आर राजेंद्रन, सुरेश पिल्लई, एसएल वर्मा, श्रीमती अंजली तिवारी, इग्नीशियस मेंडोस, एसपी बराल, शत्रुघन साहू, इंद्रजीत सिंह और एसके चक्रवर्ती ने शपथ ली।

लोक धरोहर सांस्कृतिक संस्था आहिवारा ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। धन्यवाद ज्ञापन उप महासचिव श्रीमती पायल पवार ने किया। कार्यक्रम में कॉलोनी के सैकड़ों निवासी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

विश्व रक्तदाता दिवस : दिलीप ठाकुर का कलेक्टर अभिजीत सिंह ने किया सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय दुर्ग के ओपीडी कैंपस में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दुर्ग के तत्वावधान में रक्तदाताओं के सम्मान समारोह एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऐसे रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने ब्लड बैंक एवं रक्तदान गतिविधियों में सक्रिय, सकारात्मक एवं उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इस अवसर पर श्री सत्य साईं सेवा समिति के मेडिकल कोऑर्डिनेटर दिलीप ठाकुर को उनके निरंतर सेवा कार्यों एवं रक्तदान के क्षेत्र में योगदान के लिए कलेक्टर अभिजित सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दुर्ग के अध्यक्ष डॉ. शरद पाटणकर, सचिव डॉ. मनोज दानी, सिविल सर्जन डॉ. ए.के. मिंज, ब्लड बैंक नोडल अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. जे.पी. मेश्राम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद बाघ ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. जे.पी. मेश्राम द्वारा किया गया।

समारोह में विशेष रूप से डॉ. सुधीर हिसिकर, राज आड़तिया, विजय ताम्रकार, धर्मेंद्र शाह, कुलदीप सिंह, राजेश जैन, दीपक बंसल, सतीश जैन सहित अनेक समाजसेवी एवं रक्तदाता उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में रोशन सिंह, टी.एस. एंटोनी, रूपेश कुमार, हिमांशु चंद्राकर, सती गुप्ता, धीरज इंगले, तरुणा रावत, तीरथ, सूरज, दिनेश, तरन्नुम, निशु, माला, राहुल सहित अन्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उल्लेखनीय है कि नगर की आध्यात्मिक एवं सेवा गतिविधियों में अग्रणी श्री सत्य साईं सेवा समिति द्वारा लगातार सामाजिक एवं रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं तथा समिति समय-समय पर ब्लड बैंक में रक्तदान अभियान संचालित करती रही है।

आयोजित रक्तदान शिविर में स्वयं कलेक्टर अभिजित सिंह ने भी रक्तदान कर समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया। यह रक्तदान शिविर नव दृष्टि फाउंडेशन, जेसीई दुर्ग-भिलाई, व्हेयर इंडिया एवं समर्पित परिश्रमी सामाजिक समिति जिला दुर्ग के सहयोग से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

गीतांजलि संगीत महाविद्यालय के छात्राओं ने कंपीटीशन में मारी बाजी

दुर्ग। कत्थक रॉकर्स एन युनिक इंस्टीट्यूट ऑफ डान्स, दुर्ग के तत्वाधान में देहरादून (उत्तराखंड) में आयोजित अखिल भारतीय नृत्य, संगीत एवं कला प्रतियोगिता में गीतांजली संगीत महाविद्यालय, दुर्ग की छात्रा कु. डिंकल मार्कण्डेय, कु. उत्सवी पटेल, कु. नविष्ठा ठाकुर, कु. स्वरा गजभिये (जूनियर ग्रुप) द्वारा नृत्य गुरू कु. विधि इंगले के मार्गदर्शन में कत्थक व भरतनाट्यम मिश्रित नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में यह नृत्य प्रस्तुति एक मात्र विशेष प्रस्तुति रही। इसके अलावा कु. आरना देशमुख द्वारा (जूनियर श्रेणी) में एकल कत्थक नृत्य प्रस्तुत किया गया एवं प्रथम स्थान प्राप्त किया। कलाकारों ने उक्त प्रस्तुति में प्रथम स्थान पाकर न केवल संगीत महाविद्यालय अपितु माता-पिता एवं गुरूजनों को गौरवान्वित किया है। इस सराहनीय प्रस्तुति के लिए गीतांजली संगीत महाविद्यालय दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती रत्ना नारमदेव, प्राचार्य व्ही.एन.भोले, प्रबंधक दिलीप इंगले, सहायक प्रबंधक श्रीमती आरती इंगले, सहसचिव सी.एल. सेन द्वारा छात्र कलाकारों को बधाई दी है।

मीना मनोज शर्मा ब्राम्हण सेवा समिति महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नियुक्त

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

ब्राम्हण सेवा समिति महिला प्रकोष्ठ की नई अध्यक्ष के रूप में मीना मनोज शर्मा का सर्वसम्मति से चयन किया गया है। संगीता कैलाश शर्मा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

भगवान परशुराम मंदिर में आयोजित विप्र महिलाओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में समाज की 100 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं। चर्चा के बाद चुनाव न कराकर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने पर सहमति बनी। वर्षों से समाज में सक्रिय और सबकी चहेती मीना मनोज शर्मा को एक स्वर में अध्यक्ष चुना गया। नव नियुक्त अध्यक्ष मीना शर्मा और उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने समाज की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लिया। मीना शर्मा ने कहा कि सबको साथ लेकर सर्व समाज के हित में कार्य करेंगी। जल्द ही पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। बैठक में श्रीमती संतोष शर्मा, पूर्व अध्यक्षा रमा शर्मा, मीरा शर्मा समेत शताधिक महिलाएं मौजूद रहीं।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.कं.../अ/6 वर्ष 2025-26)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक -रेखा तिवारी आ./ध.प. निशिकांत तिवारी निवासी घासीदास नगर भिलाई द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.नं. 46. रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 712/1 रकबा 0.010 हे. भूमि को रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर दिनांक 07/02/23 के आधार पर विक्रेता खेदूराम आ० बनुउ, आम मु. खेदिया आ. बनुऊ से क्रय किया गया है, कि रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 25/06/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10/06/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

महावीर चौक फ्लाईओवर के नीचे 17 जून तक प्रदर्शित होंगी केंद्र सरकार की उपलब्धियां, सांसद संतोष पाण्डेय व महापौर मधुसूदन यादव ने किया उद्घाटन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव-रायपुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा 15 से 17 जून 2026 तक राजनांदगांव के महावीर चौक स्थित फ्लाईओवर के नीचे केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदशर्नी का शुभारंभ सांसद संतोष पाण्डेय एवं महापौर मधुसूदन यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदशर्नी का अवलोकन कर विभिन्न विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शित जानकारी का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही।

फोटो प्रदशर्नी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं जनहितकारी नेतृत्व में देश तथा छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों और शासन की योजनाओं के प्रभाव को आकर्षक चित्रों एवं जानकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रदशर्नी में किसान कल्याण, गरीब कल्याण, अधोसंरचना विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास तथा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण जैसे विभिन्न विषयों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।

प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरण, किसानों को लागत से कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, कृषि निर्यात में वृद्धि तथा लगभग 2 करोड़ किसानों एवं 3 लाख व्यापारियों के ई-नाम पोर्टल से जुड़ने संबंधी जानकारी प्रदर्शित की गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण, सेमीकंडक्टर निर्माण, मुफ्त राशन योजना तथा 9 करोड़ लाभार्थियों के पोषण क्रय जैसे जनकल्याणकारी कार्यों को भी दर्शाया गया है।

देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयासों को भी प्रदर्शनी में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देते हुए लगभग 38,400 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड रक्षा निर्यात की जानकारी दी गई है। अधोसंरचना विकास के अंतर्गत विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज, समुद्र पर निर्मित अटल सेतु, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक विस्तार तथा वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रदर्शित किया गया है।

प्रदर्शनी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल अभियान, 3 करोड़ लखपति दीदी पहल, युवा शक्ति सशक्तिकरण तथा अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण सहित विभिन्न उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है। साथ ही एलईडी स्क्रीन के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी स्थल पर आगंतुकों को जनमन पत्रिका एवं सुशासन के नवीन आयाम पुस्तक का भी वितरण किया जा रहा है।

इस अवसर पर दिनेश गांधी, राजेश श्यामकर, रघु शर्मा, बलवंत साहू, प्रखर श्रीवास्तव, आशुतोष सिंह, ईशान शर्मा, अरविंद बैद, हेतल भोजानी, सज्जन सिंह ठाकुर, सतीश यादव, अश्विनी, परमेश्वर लहरे, मनोज साहू सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खास खबर

मंत्री लखनलाल देवांगन ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-कोरबा

प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के ग्राम भूलसीडीह स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों, लेक्चर हॉल, अकादमिक ब्लॉक तथा डीन कार्यालय का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से निर्माण कार्यों एवं उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंत्री श्री देवांगन को मेडिकल कॉलेज में विकसित की जा रही क्लिनिकल एवं पैरा-क्लिनिकल प्रयोगशालाओं, एनाटॉमी तथा फिजियोलॉजी विभाग सहित अन्य आवश्यक अधोसंरचनाओं के संबंध में जानकारी दी। मंत्री श्री देवांगन ने सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आगामी जनवरी माह तक सभी कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में सेवा, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर अनेक विकास कार्य किए गए हैं। उनके मार्गदर्शन में कोरबा जिले में भी विभिन्न विकास परियोजनाएं साकार हुई हैं, जिनमें भूलसीडीह मेडिकल कॉलेज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान महापौर कोरबा श्रीमती संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश नाग सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण अधिकारी उपस्थित थे।

बेमेतरा जिले में दलहन के रकबे में चार गुना की वृद्धि, विकासखंड नवागढ़ के ग्राम हरदी के किसान इंद्रकुमार

रायपुर-बेमेतरा। छत्तीसगढ़ शासन की मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस योजना बेमेतरा जिले में दलहन उत्पादन को नई ऊंचाई दे रही है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन और उन्नत खेती तकनीकों के चलते जिले में ग्रीष्मकालीन उड़द-मूंग की खेती का रकबा एक वर्ष में चार गुना से अधिक बढ़ गया है। पिछले वर्ष 285 हेक्टेयर में होने वाली खेती इस वर्ष बढ़कर 1191 हेक्टेयर तक पहुंच गई है। विकासखंड नवागढ़ के ग्राम हरदी के किसान इंद्रकुमार ने ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती कर सफलता की नई मिसाल पेश की है। कृषि विभाग के अनुसार उन्हें 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलने की संभावना है। वहीं कोरकापारा के किसान शिवशंकर वर्मा को 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन का अनुमान है। दोनों किसानों ने उन्नत बीजों और वैज्ञानिक खेती पद्धतियों को अपनाकर बेहतर परिणाम हासिल किए हैं।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि उड़द और मूंग जैसी दलहन फसलें किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार करती हैं। जिले में करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1280 किसानों द्वारा उड़द फसल के प्रदर्शन लगाए गए हैं, जिससे अन्य किसान भी आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बेमेतरा में दलहन खेती का बढ़ता दायरा इस बात का संकेत है कि वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

संवेदनशीलता, निष्पक्षता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का करें निर्वहन : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय से प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने की मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनकी सफलता के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कि प्रशासनिक सेवा जनसेवा का सबसे प्रभावी माध्यम है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए प्रत्येक निर्णय में जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे संवेदनशीलता, निष्पक्षता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान का वास्तविक महत्व तभी है, जब उसका उपयोग समाज और आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं से परिपूर्ण प्रदेश है। यहां के लोग सरल, सहज, मेहनती और आत्मीय स्वभाव के हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों, तेजी से विकसित हो रही कनेक्टिविटी, पर्यटन की संभावनाओं, नक्सल उन्मूलन की सफलता तथा राज्य के विकास की यात्रा से अवगत कराया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय परंपराओं और विकास के नए अवसरों पर भी अपने अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को कहा कि ईमानदारी, निष्ठा और जनहित की भावना से लिया गया प्रत्येक निर्णय प्रदेश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बस्तर संभाग के सुकमा और बीजापुर जिलों सहित सरगुजा संभाग के जशपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों का भ्रमण करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनजीवन, संस्कृति, विकास गतिविधियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया तथा मां दंतेश्वरी के दर्शन भी किए।

अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विविधताओं, सांस्कृतिक समृद्धि और आत्मीयता से भरपूर प्रदेश है। यहां के लोगों के स्नेह, जनजातीय परंपराओं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की संभावनाओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा के माध्यम से जनहित में कार्य करना उनके लिए गौरव और जिम्मेदारी दोनों है।

मुलाकात के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशासनिक सेवा की तैयारी से जुड़े अनुभव, चुनौतियां और प्रेरणादायक प्रसंग भी साझा किए। मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्हें निरंतर सीखते रहने, जमीनी स्तर से जुड़े रहने तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर कार्य करने की प्रेरणा दी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी गोकुल आरके, वी. यशवंत नायक एवं ईशांत जायसवाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तीनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ है। जिला प्रशिक्षण पर रवाना होने से पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एवं अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, संचालक टीसी महावर तथा संयुक्त संचालक प्रणव सिंह उपस्थित थे।

दंतेवाड़ा को मिली डेढ़ करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा जिले के नगरीय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने 1 करोड़ 49 लाख 11 हजार रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पित कार्यों में आधुनिक चौपाटी, व्यावसायिक गुमटियां, आकांक्षी शौचालय तथा नवीन आंगनबाड़ी भवन शामिल हैं। इन सुविधाओं से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा तथा महिला एवं बाल विकास गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा एक प्रमुख धार्मिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। आने वाले समय में यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को दंतेवाड़ा नगर और मंदिर क्षेत्र के समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

श्री कश्यप ने नगर के सीवरेज प्लांट से निकलने वाले पानी के सीधे नदी में प्रवाहित होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल को उपचारित (ट्रीटमेंट) करने के बाद ही नदी में छोड़ा जाए अथवा आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उन्होंने भैरम बाबा मंदिर के समीप नदी तट पर हो रहे कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग को शीघ्र पिचिंग कार्य की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

नगरपालिका द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए मंत्री श्री कश्यप ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि नगर के प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महापुरुषों के नाम पर किया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा दंतेवाड़ा शहर में एक आकर्षक घड़ी चौक (क्लॉक टॉवर) का निर्माण कराया जाएगा। बच्चों और युवाओं के मनोरंजन तथा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्विमिंग पूल परिसर में वाटर स्लाइडर की सुविधा विकसित करने की भी घोषणा की गई।

उद्योग मंत्री ने पौने 37 करोड़ रूपए के जलप्रदाय योजना विस्तार कार्य का किया भूमिपूजन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-कोरबा

वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने नगर पालिक निगम कोरबा के पौने 37 करोड़ रूपये की लागत वाले जलप्रदाय योजना विस्तार कार्य का भूमिपूजन किया। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा जिला खनिज न्यास मद (डीएमएफ) से 36 करोड़ 73 लाख रूपये की लागत से जलप्रदाय योजना का विस्तार कार्य किया जाना हैं, इसके अंतर्गत 20 एमएलडी के जलउपचार संयंत्र के साथ-साथ इमलीडुग्गू में 12 लाख 60 हजार लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी, दादरखुर्द में 22 लाख 50 हजार लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी एवं रूमगरा में 10 लाख 80 हजार लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी यानी उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण किया जाएगा, वहीं 15.3 किलोमीटर पाईप लाईन भी बिछाई जाएगी। योजना के पूर्ण होने पर इमलीडुग्गू मोतीसागरपारा, भिलाईखुर्द, बरबसपुर, कर्रानाला, मानिकपुर, रूमगरा, ढेलवाडीह, खरमोरा, दादरखुर्द, बेलगिरी बस्ती में निवासरत नागरिकों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ निचले स्तर पर स्थित बस्तियों जहाँ पर लो प्रेशर के फलस्वरूप पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही थी, उन समस्त स्थानों में निर्वाध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी तथा नगर निगम कोरबा क्षेत्र की लगभग 60 हजार जनसंख्या इस कार्य से लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज इस महत्वपूर्ण कार्य का भूमिपूजन किया गया है, इस कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात निगम क्षेत्र की ऐसी बस्तियों जहाँ पानी की किल्लत थी तथा पानी की कम आपूर्ति होती थी, वहाँ पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सकेगी तथा पानी की किल्लत दूर होगी। महापौर श्रीमती राजपूत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में देश व प्रदेश का चहुमुंखी विकास हो रहा है, वहीं कोरबा के विकास के लिये उपमुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पेयजल योजना विस्तार का यह कार्य निगम की पेयजल व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा तथा आमनागरिकों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उन्होने कहा कि विगत 12 साल में केन्द्र सरकार के द्वारा देश व प्रदेश का तेजी से विकास किया गया है, 12 साल में लाखों किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आयें हैं तथा 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना में निःशुल्क इलाज हो रहा है।

भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी केसाथ ही पार्षद अशोक चावलानी, नरेन्द्र देवांगन, एमआईसी सदस्य हितानंद अग्रवाल, फिरतराम साहू, उवर्शी राठौर, अजय गोंड़, सरोज शांडिल्य, अजय कुमार चन्द्रा, पार्षद रूबीदेवी सागर, धनश्री साहू, युगल कैवर्त, सुनीता चौहान, सुलोचना यादव, राधा महंत, राकेश वर्मा, सीमा कंवर, उपेन्द्र पटेल, ईश्वर पटेल, प्रताप सिंह कंवर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, महामंत्री अजय विश्वकर्मा, सुफलदास महंत, दिनेश शर्मा, सुकेश दलाल, विनय जायसवाल, प्रदीप मजूमदार, राकेश खरे, आत्माराम गंधर्व, रितू जायसवाल, नरेन्द्र पाटनवार, आकाश श्रीवास्तव, मनोज सिंह राजपूत, अनिल यादव आदि के साथ काफी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

वन मंत्री केदार कश्यप ने 18 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, परिवहन एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने जिले को 18 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण का शुभारंभ करते हुए 16 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा 2 करोड़ 9 लाख रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री एवं प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए।

वन मंत्री श्री कश्यप ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं अधोसंरचना विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें मिरतुर और बेदरे में ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण, उसूर में वरिष्ठ कृषि अधिकारी भवन, आवापल्ली एवं कुटरू में शासकीय महाविद्यालय भवन, भैरमगढ़ महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा दुगईगुड़ा से चिंताकोंटा तक सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शिक्षा, कृषि सेवाओं और आवागमन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति प्राप्त होगी।

लोकार्पित कार्यों में जिला अस्पताल परिसर में रैन बसेरा, दाल-भात केंद्र, अत्याधुनिक अटल आरोग्य लैब, कार्यालय सह गोदाम भवन, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, पुलिया निर्माण तथा शैक्षणिक संस्थानों में तार फेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। अटल आरोग्य लैब में अब 134 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

मलेरिया मुक्त अभियान का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण का शुभारंभ किया गया। अभियान के माध्यम से जिले में मलेरिया नियंत्रण, समय पर जांच और उपचार के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिससे लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मिल रहा योजनाओं का लाभ

कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया। वहीं निष्क्षय योजना के तहत पोषण आहार फूड बॉक्स, पुनर्वासित परिवारों को आयुष्मान कार्ड, गर्भवती महिलाओं को जच्चा-बच्चा कार्ड तथा दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्रदान की गई।

विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है बीजापुर

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजापुर में अब विकास की नई धारा बह रही है। पहले जिन क्षेत्रों तक पहुंचना कठिन था, वहां आज सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनकल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

आयुष्मान भारत सहित कई योजनाएं बदल रहीं जीवन

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं से समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बीजापुर आने वाले वर्षों में विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता सोम पुजारी, कलेक्टर विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, डीएफओ डॉ. सागर यादव, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता चौबे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

संपादकीय

भस्मासुर न बने एआई नियमन की पहल संग साइबर सुरक्षा बढ़े

पिछले दिनों पोप लियो के उसे बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर गहरी चिंता जतायी थी। उन्होंने इस अत्याधुनिक तकनीक के युद्धों में घातक प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा था कि कोई भी एल्गोरिद्म युद्ध को नैतिक नहीं बना सकता। जाहिर है उन्होंने एआई के खतरों को महसूस करते हुए दुनिया को इसके घातक प्रभावों से अवगत कराया। कहीं न कहीं उनके इस बयान के गहरे निहितार्थ हैं कि एआई को इंसानी नियंत्रण में रखने की जरूरत है।

जो मानवीय मूल्यों की रक्षा और नैतिकता को अक्षुण्ण रखने के लिये भी जरूरी है। हाल के दिनों में दुनिया में साइबर अपराधों में वृद्धि, वैज्ञानिक डेटा का दुरुपयोग और एआई आधारित हथियारों का बोलबाला बढ़ा है। कह सकते हैं, पूरी दुनिया एआई को लेकर भय व आशंकाओं में जी रही है। जिसकी प्रतिध्वनि पोप लियो के बयान में भी झलकती है। यह महज संयोग है या पोप के बयान का प्रभाव कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कायर्कारी आदेश जारी कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है।

निश्चय ही यह अमेरिकी नीतियों में बड़ा बदलावा है, क्योंकि अब तक चीन से आगे निकलने की होड़ में अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को बेलगाम छूट दे रखी थी। अमेरिकी सरकार के इस नये आदेश के अनुसार अब अमेरिकी एआई कंपनियां अपने नये मॉडल को सार्वजनिक करने से पहले सरकार को समीक्षा के लिये तीन दिन तक का समय स्वेच्छा से देंगी। सरकार का एक समीक्षा केंद्र एआई मॉडल द्वारा खोजी गई तकनीक की सुरक्षा खामियों की समीक्षा करेगा। निस्संदेह, यह पहल उन पुराने प्रस्तावों से अलग है जो प्रमुख एआई मॉडलों को सरकारी नियंत्रण में लाने की बात करते थे। यह एक अनिवार्य जांच प्रक्रिया होगी। वैसे भी तकनीकी कंपनियों पर इस बात के लिये भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे खुद नियंत्रण की पहल करेंगी।

हालांकि, अमेरिका में एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि इस नियमन से अमेरिका की तकनीकी बढ़त कम हो सकती है। वे सरकारी दखल का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी अदालत में कुछ एआई कंपनियों को मानवीय जीवन में हस्तक्षेप के लिये कटघरे में खड़ा भी किया गया है। बहरहाल, अमेरिका में विरोध के बावजूद ट्रंप ने एआई को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। हालांकि,इस पहल को पूरी तरह कारगर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी नियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है। खास तौर से , एक अमेरिकी कंपनी के नये मॉडल की घोषणा के बाद से ही एआई सुरक्षा और नवाचार के बीच संतुलन बनाये रखने के लिये एक औपचारिक निगरानी तंत्र विकसित करने की जरूरत पर बल दिया जा रहा।

दरअसल यह नई घोषणा विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कंपनी ने अप्रैल में दावा किया था कि उसकी नई खोज दुनिया के विभिन्न देशों की साइबर सुरक्षा की कमजोरियों की पहचान करने और उसका लाभ उठाने में सक्षम है। निश्चय ही इसके गंभीर परिणामों को लेकर पूरी दुनिया में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। एक तरफ दुनिया की तमाम सरकारें और व्यवसाय सॉफ्टवेयर प्रणालियों को सुरक्षित करने और सभी सुरक्षा उपाय लागू करने के दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं, वहीं नई एआई खोजों से व्यापक दुरुपयोग की आशंका पैदा हो गई हैं।

यही वजह है कि दुनिया के देशों में लोगों में एआई को लेकर नकारात्मक धारणा बन रही है। एक तो रोजगार के अवसरों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लेकर पहले ही चिंता व्यक्त की जा रही हैं, दूसरी ओर नई सेंधमारी की आशंकाएं उसे और गंभीर बना रही हैं। यही वजह है कि आम लोगों में इस ताकतवर तकनीक को लाभ के बजाय हानि के रूप में देखा जा रहा है। जिसकी झलक पोप के हालिया बयान के रूप में देखी जा रही है। बहरहाल, भारत के लिये अमेरिकी रणनीति में बदलाव एक बड़ा सबक है। भारत को भी इसी तरह से अधिक साइबर सुरक्षा बढ़ाने और एआई पेशेवरों को नियुक्त करने की जरूरत होगी। हमारे लिये बुनियादी ढांचे का संचालन करने वाले संस्थानों में मजबूत में मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणालियों को सुनिश्चित करना जरूरी होगा।

महंगाई का बढ़ता साया, मध्यम व निम्न वर्ग के लिए परेशानी

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में महंगाई केवल एक आर्थिक शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के दैनिक जीवन से जुड़ी एक ऐसी वास्तविकता है जो उनकी आय, बचत, भोजन, शिक्षा और भविष्य की योजनाओं को सीधे प्रभावित करती है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टों और बाजार के रुझानों से स्पष्ट है कि मार्च के बाद से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। खाद्य तेल, साबुन, डिटर्जेंट, कॉफी, हैंडवॉश, नमकीन, शैंपू और दालों जैसे आवश्यक उत्पादों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई वृद्धि ने आम उपभोक्ता की परेशानी को और बढ़ा दिया है।

महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव मध्यम और निम्न आय वर्ग पर पड़ता है। इन वर्गों की आय सीमित होती है और उनके खर्च का बड़ा हिस्सा भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक जरूरतों पर खर्च होता है। जब रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो इनके पास बचत के अवसर कम हो जाते हैं। परिणामस्वरूप परिवारों को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है या फिर कर्ज का सहारा लेना पड़ता है।

रिपोर्ट के अनुसार खाद्य तेलों की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। जहां जून में इनमें 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं मार्च के बाद अब तक यह वृद्धि 20 से 25 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। भारत खाद्य तेलों की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और खाद्य तेलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और परिवहन लागत में वृद्धि ने खाद्य तेलों को महंगा बना दिया है।

महंगाई का दूसरा महत्वपूर्ण कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल भी महंगे हुए हैं। ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जब ईंधन महंगा होता है तो परिवहन लागत बढ़ जाती है। इसका असर खेतों से मंडियों तक, फैक्ट्रियों से बाजारों तक और गोदामों से उपभोक्ताओं तक हर स्तर पर दिखाई देता है। फलस्वरूप लगभग हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है।

आज कंपनियां भी बढ़ती लागत के दबाव में हैं। कच्चे माल, बिजली, परिवहन और पैकेजिंग की लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में कंपनियां दो तरीके अपनाती हैं— या तो उत्पादों के दाम बढ़ाती हैं या पैकेट का आकार घटा देती हैं। उपभोक्ताओं को अक्सर यह महसूस नहीं होता कि समान कीमत पर मिलने वाला उत्पाद अब पहले से कम मात्रा में उपलब्ध है। इसे अथर्शास्त्र की भाषा में श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। यह भी महंगाई का एक छिपा हुआ रूप है।

महंगाई का सबसे स्पष्ट असर रसोई पर दिखाई देता है। एक मध्यमवर्गीय परिवार का मासिक रसोई बजट यदि पहले 15 हजार रुपये था तो कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह खर्च अब 17 से 18 हजार रुपये तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन सालभर में यह अतिरिक्त खर्च हजारों रुपये तक पहुंच जाता है। जिन परिवारों की आय स्थिर है, उनके लिए यह स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। खेती में डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों की लागत बढ़ने से कृषि उत्पादन महंगा हुआ है। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, जबकि उपभोक्ता को वही उत्पाद महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। इस प्रकार महंगाई का बोझ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर पड़ता है, जबकि बीच की आपूर्ति श्रृंखला और बाजार संरचना अधिक लाभ अर्जित करती है।

महंगाई का सामाजिक प्रभाव भी गहरा होता है। जब आवश्यक वस्तुएं महंगी होती हैं तो परिवार सबसे पहले मनोरंजन, पर्यटन और विलासिता के खर्च में कटौती करते हैं। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों पर भी असर पड़ने लगता है। कई परिवार बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर, शिक्षा पर होने वाले खर्च में कमी भविष्य की मानव पूंजी को प्रभावित करती है।

आर्थिक दृष्टि से नियंत्रित महंगाई को विकास का संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे मांग और उत्पादन में वृद्धि का संकेत मिलता है। लेकिन जब महंगाई आय वृद्धि से अधिक तेजी से बढ़ने लगे तो यह आर्थिक असंतुलन पैदा करती है। वतर्मान स्थिति में यही चिंता सामने आ रही है। वेतन और रोजगार की वृद्धि दर उतनी तेज नहीं है जितनी तेजी से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे वास्तविक क्रय शक्ति कम हो रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर कदम उठाते हैं। ब्याज दरों में परिवर्तन, आयात शुल्क में कमी, आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर निगरानी और बाजार में आपूर्ति बढ़ाने जैसे उपाय किए जाते हैं। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भू-राजनीतिक तनावों के कारण कई बार इन प्रयासों का प्रभाव सीमित रह जाता है।

वर्तमान परिस्थितियों में सरकार को बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। खाद्य तेलों और आवश्यक वस्तुओं के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का विस्तार, भंडारण सुविधाओं का विकास और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही जमाखोरी और कृत्रिम मूल्य वृद्धि पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। पेट्रोलियम उत्पादों पर कर संरचना की समीक्षा भी उपभोक्ताओं को राहत देने में सहायक हो सकती है।

उपभोक्ताओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। अनावश्यक खरीदारी से बचना, बजट आधारित खर्च करना, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना और बचत की आदत विकसित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। डिजिटल माध्यमों से कीमतों की तुलना कर बेहतर विकल्प चुनना भी खर्च कम करने में मददगार हो सकता है।

महंगाई केवल आर्थिक आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीय परिवारों के जीवन स्तर, पोषण, शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा प्रश्न है। यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इसी प्रकार निरंतर वृद्धि होती रही तो इसका प्रभाव केवल घरेलू बजट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की गति पर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं—तीनों को मिलकर संतुलित और दीघर्कालिक समाधान तलाशने होंगे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विकास की चमक केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि आम आदमी की थाली, रसोई और जेब में भी दिखाई दे। जब तक महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा। महंगाई की चुनौती केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की साझा चुनौती है, जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

क्या सोने में फिर लौटेगा 1970 के दशक जैसा महाबुल रन?

केपी मलिक

सोना सदियों से केवल एक धातु नहीं, बल्कि आर्थिक अनिश्चितता के समय निवेशकों का सबसे भरोसेमंद आश्रय माना जाता रहा है। जब दुनिया युद्ध, महंगाई, मंदी या वित्तीय संकटों से घिरती है, तब निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ जाता है। आज भी वैश्विक परिस्थितियां कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं। ईरान-इजराइल तनाव, भू-राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती सरकारी देनदारियां, मुद्रास्फीति की चिंताएं और वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार के बीच यह सवाल फिर उठ रहा है कि क्या सोना 1970 के दशक जैसी ऐतिहासिक तेजी दोहरा सकता है?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सोना पहले ही असाधारण प्रदर्शन कर चुका है। भारत में जहां 2023 के आसपास सोना लगभग 63 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, वहीं 2026 तक यह करीब 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। यानी तीन वर्षों में लगभग तीन गुना वृद्धि। लेकिन हाल के महीनों में, जब मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा और वैश्विक अनिश्चितताएं बनी रहीं, तब भी सोना अपने उच्चतम स्तर से लगभग 20 प्रतिशत तक फिसल गया। इससे निवेशकों के मन में यह दुविधा पैदा हो गई है कि क्या यह केवल अस्थायी गिरावट है या फिर बड़ी कमजोरी की शुरुआत?

1970 का दशक सोने के इतिहास का सबसे चर्चित दौर माना जाता है। उस समय अमेरिकी डॉलर और सोने के बीच का स्थायी संबंध टूट गया था। 1971 में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था समाप्त हुई और डॉलर पूरी तरह फिएट मुद्रा बन गया। इसके बाद तेल संकट, ऊंची महंगाई और आर्थिक अस्थिरता ने निवेशकों को सोने की ओर धकेला। परिणामस्वरूप सोने की कीमत लगभग 35 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 850 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। यह वृद्धि केवल एक बुल रन नहीं थी, बल्कि आधुनिक वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी कमोडिटी रैलियों में से एक थी।

आज कई विश्लेषक वर्तमान परिस्थितियों की तुलना उसी दौर से कर रहे हैं। अमेरिका सहित कई देशों पर रिकॉर्ड स्तर का कर्ज है। केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। डॉलर के विकल्प खोजने की चर्चाएं बढ़ रही हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से अनेक देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ाया है। चीन, भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। यह मांग कीमतों को दीघर्कालिक समर्थन प्रदान करती है।

लेकिन इतिहास का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1970 के दशक की ऐतिहासिक तेजी के बाद सोने ने लंबा और दर्दनाक सुधार देखा था। 1980 में शिखर पर पहुंचने के बाद अगले दो दशकों तक सोने की कीमतें लगभग स्थिर रहीं और कई निवेशकों को वास्तविक रिटर्न भी नहीं मिला। यही वह चेतावनी है जिसे विशेषज्ञ आज बार-बार दोहरा रहे हैं। किसी भी परिसंपत्ति में लगातार तेज वृद्धि के बाद सुधार या ठहराव स्वाभाविक होता है।

वर्तमान समय में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक अमेरिकी ब्याज दरें हैं। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तब निवेशकों को बॉन्ड और अन्य निश्चित आय वाले साधनों में बेहतर रिटर्न मिलता है। ऐसे में सोने का आकर्षण कुछ कम हो जाता है क्योंकि सोना कोई ब्याज या लाभांश नहीं देता। यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखता है, तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। दूसरी ओर यदि आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ती है और दरों में कटौती शुरू होती है, तो सोना फिर मजबूत उछाल दिखा सकता है।

ईरान-इजराइल तनाव भी सोने की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। सामान्यतः युद्ध और भू-राजनीतिक संकट सोने के लिए सकारात्मक माने जाते हैं। लेकिन बाजार केवल घटनाओं पर नहीं, बल्कि उनकी संभावित अवधि और प्रभाव पर प्रतिक्रिया देता है। यदि तनाव सीमित रहता है तो उसका प्रभाव अस्थायी हो सकता है। वहीं यदि संकट व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदलता है और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है, तो सोना फिर से सुरक्षित निवेश के रूप में बड़ी मांग आकर्षित कर सकता है।

भारत के संदर्भ में स्थिति थोड़ी अलग है। भारतीय निवेशकों के लिए सोने की कीमत केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार से नहीं, बल्कि रुपये की विनिमय दर से भी प्रभावित होती है। यदि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें स्थिर रहने के बावजूद भारत में सोना महंगा हो सकता है। इसलिए भारतीय निवेशकों को केवल वैश्विक कीमतों पर नहीं, बल्कि मुद्रा विनिमय दरों पर भी नजर रखनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोने को लेकर अति उत्साह और अति निराशा, दोनों से बचना चाहिए। इतिहास बताता है कि सोना लंबी अवधि में संपत्ति संरक्षण का अच्छा माध्यम है, लेकिन यह हमेशा एकतरफा ऊपर नहीं जाता। कई बार वर्षों तक कीमतें स्थिर रह सकती हैं और कई बार तेज गिरावट भी आ सकती है। इसलिए केवल भय, युद्ध या अफवाहों के आधार पर निवेश निर्णय लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

बहरहाल, 1970 के दशक जैसा महाबुल रन दोहराया जाएगा या नहीं, इसका निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि दुनिया एक बार फिर आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। यही कारण है कि सोना निवेशकों के रडार पर बना हुआ है। फिर भी इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब हर कोई केवल तेजी की बात करने लगे, तब सावधानी बरतना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। सोना भविष्य में नई ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन उसके रास्ते में उतार-चढ़ाव और जोखिम भी उतने ही बड़े होंगे। इसलिए निवेशकों को भावनाओं के बजाय तथ्यों, संतुलन और दीघर्कालिक दृष्टिकोण के साथ निर्णय लेना चाहिए।

चरमराता परीक्षा सिस्टमः पेपर लीक का उद्योग और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़

आलोक बाजपेयी

भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश हमारी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन आज की कड़वी हकीकत यह है कि इसी युवा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की चरमराती परीक्षा प्रणाली के कारण गहरे अवसाद, अनिश्चितता और मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। लखनऊ के इको गार्डन से लेकर देश के कोने-कोने में युवाओं का सड़कों पर उतरना इस बात का गवाह है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक का एक ऐसा संगठित उद्योग खड़ा हो चुका है, जिसने भारत के परीक्षा तंत्र को पूरी तरह खोखला कर दिया है।

एक राष्ट्रीय संकट और संगठित अपराध

पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कोई साल या महीना नहीं बीता, जब किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के लीक होने या उसमें धांधली की खबर न आई हो। नीट, नेट, पुलिस भर्ती परीक्षा, रेलवे, शिक्षक पात्रता परीक्षा से लेकर राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं तक—हर जगह सेंधमारी हो रही है। यह कोई प्रशासनिक ढीलापन या छिटपुट लापरवाही नहीं है; यह एक अरबों रुपये का संगठित अपराध बन चुका है। सरकारें पेपर लीक होने के बाद कानून बनाने या परीक्षा रद्द करने की औपचारिकता तो पूरी कर लेती हैं, लेकिन इस संगठित तंत्र की जड़ों पर प्रहार करने में पूरी तरह विफल रही हैं।

पेपर लीक का फैला जाल

मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात-आठ सालों में देश के अलग-अलग राज्यों में 70 से अधिक बड़ी परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। इन घोटालों के कारण लगभग 1.7 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका है। नीट, यूजीसी-नेट, यूपी पुलिस भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, रेलवे और विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में जिस तरह संगठित गिरोहों ने सेंधमारी की है, उसने साबित कर दिया है कि परीक्षा माफिया, प्रिंटिंग प्रेस, निजी परीक्षा केंद्रों

और प्रशासनिक अधिकारियों का एक ऐसा अभेद्य गठजोड़ तैयार हो चुका है, जो मोटी रकम के बदले लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य का सौदा दिन-दहाड़े कर रहा है।

सिस्टम की नाकामी और लचर जवाबदेही

जब एक परीक्षा लीक होती है या उसमें धांधली के कारण उसे रद्द करना पड़ता है, तो केवल एक पेपर रद्द नहीं होता। उसके साथ एक छात्र की सालों की मेहनत, उसके गरीब माता-पिता की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपये और पूरे परिवार की उम्मीदें जमींदोज हो जाती हैं। सबसे शमर्नाक बात यह है कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदाओं के बाद भी जवाबदेही तय नहीं की जाती। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी शीर्ष संस्थाओं से लेकर राज्य के भर्ती बोर्डों तक, कोई भी अधिकारी इस विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। परीक्षा रद्द होने के बाद नई तारीखों का महीनों तक इंतजार करना, कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटना और अंतहीन कानूनी प्रक्रियाओं में उलझना भारतीय छात्रों की नियति बन चुका है।

युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ : एक अदृश्य महामारी

परीक्षा प्रणाली की यह सड़न सीधे तौर पर युवाओं को मानसिक रूप से बीमार बना रही है: इसमें पहला तनाव भविष्य की अनिश्चितता का होता है. 20 से 30 वर्ष की उम्र का स्वर्णिम समय, जो देश के निर्माण में लगना चाहिए था, वह सिर्फ परीक्षाओं के चक्रव्यूह में उलझकर रह गया है। पारिवारिक और सामाजिक दबाव भी भयावह होता है। सालों तक एक ही परीक्षा की तैयारी करने और फिर पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द होने से युवा अपने ही परिवार के सामने खुद को नाकाम महसूस करने लगते हैं। गंभीर अवसाद इन सबका सामूहिक और सबसे सामान्य दुष्परिणाम है. कोचिंग हब बन चुके शहरों (जैसे कोटा, प्रयागराज, मुखर्जी नगर) से आने वाली छात्रों की आत्महत्या की खबरें अब महज आंकड़े बनकर रह गई हैं। यह परीक्षा प्रणाली छात्रों की मेधा का परीक्षण नहीं कर रही, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य की बलि ले रही है।

युवाओं की आत्महत्या : एक संस्थागत हत्या

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स ने भी देश में छात्र आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को एक संस्थागत संकट माना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, यानी हर दिन लगभग 35 से अधिक युवा अपनी जान दे रहे हैं। सालों तक एक ही परीक्षा की तैयारी करने, अपनी जवानी के सबसे महत्वपूर्ण 5-6 साल एक बंद कमरे में गुजारने और फिर अंत में पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द होने से युवा भीतर से टूट जाते हैं।

जवाबदेही से भागती सरकार : धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं?

लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत ह्यजवाबदेहीह्ल है, लेकिन भारतीय परीक्षा तंत्र में यह शब्द पूरी तरह गायब हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत आने वाली देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में ऐतिहासिक धांधली और पेपर लीक के बड़े-बड़े सबूत सामने आने के बाद भी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। विपक्ष और करोड़ों छात्रों के भारी आक्रोश के बावजूद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ना तो दूर, सरकार लगातार इस विफलता पर लीपापोती करने में जुटी रही। जब व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे राजनेता और नीति-निर्माता अपनी विफलता को स्वीकार करने और कुर्सी छोड़ने से इनकार कर देते हैं, तो यह सीधे तौर पर देश के युवाओं के घावों पर नमक छिड़कने जैसा होता है। यह रवैया संदेश देता है कि सरकार के लिए नेताओं की कुर्सियां युवाओं के भविष्य से कहीं अधिक कीमती हैं।

आज तक किसी बड़े जिम्मेदार को सजा नहीं

पेपर लीक होने के बाद सरकारें आनन-फानन में कड़े कानून बनाने, सीबीआई जांच सौंपने या कुछ छोटे-मोटे दलालों और डमी कैंडिडेट्स को गिरफ्तार करने का ढोंग तो रचती हैं, लेकिन आज तक इतिहास में किसी भी बड़े मगरमच्छ—चाहे वह कोई बड़ा नेता हो, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी हो या परीक्षा बोर्ड का चेयरमैन—को ऐसी मिसाल बनने वाली सख्त सजा नहीं मिली है जो दूसरों के लिए सबक बने। जांच के नाम पर मामलों को सालों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कड़े कानून केवल कागजों पर धूल फांक रहे हैं क्योंकि जब तक परीक्षा कराने की पूरी प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा को पारदर्शी नहीं बनाया जाएगा, और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफियाओं की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक कोई भी कागजी कानून इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता।

सत्रह वर्ष का एक बच्चा बनाम तमाम जाँच एजेंसियाँ

इस सड़ते हुए परीक्षा तंत्र की पोल तब और भी शमर्नाक तरीके से खुली, जब राँची के महज 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने वह कर दिखाया जो बड़ी-बड़ी जाँच एजेंसियाँ नहीं कर पाईं। अपनी 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी मिलने पर, सार्थक ने केवल शिकायत नहीं की, बल्कि खुद एक इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाई। उसने CBSE के On-Screen Marking (OSM) टेंडर के सैकड़ों पन्नों के दस्तावेजों का विश्लेषण किया और पाया कि कैसे एक दागी कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए टेंडर के नियमों में 15 बार बदलाव किए गए और खराब प्रदर्शन वाले क्लॉज हटा दिए गए। उसकी यह रिपोर्ट इतनी ठोस थी कि उसे शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने गवाही देने के लिए दिल्ली बुलाया गया। 2 जून 2026 को संसद के एनेक्सी में, जब एक स्कूल यूनीफॉर्म पहनने वाले बच्चे ने देश के शीर्ष अधिकारियों और सांसदों के सामने 7 पन्नों का डॉसियर रखकर सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाईं, तो यह साबित हो गया कि हमारी परीक्षा व्यवस्था न केवल अक्षम है, बल्कि नैतिक रूप से भी खोखली हो चुकी है।

केवल कड़े कानून नहीं, पूरी परीक्षा प्रक्रिया के ढांचागत सुधार जरुरी

एक स्वतंत्र और तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए, जो प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर मूल्यांकन तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करे। पेपर लीक और भर्ती घोटालों से जुड़े मामलों के लिए समयबद्ध विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित न रहें। यदि किसी परीक्षा को प्रशासनिक विफलता या सुरक्षा चूक के कारण रद्द करना पड़ता है, तो अभ्यर्थियों को यात्रा, आवास और तैयारी पर हुए खर्च के लिए उचित आर्थिक मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, भर्ती प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता तंत्र विकसित किया जाए। जब तक व्यवस्था अभ्यर्थियों के समय, श्रम और मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही मूल्यवान नहीं मानेगी जितना वह अपनी संस्थागत प्रतिष्ठा को मानती है, तब तक सुधार अधूरे ही रहेंगे।

युवाओं के धैर्य की परीक्षा बंद हो

एक राष्ट्र के रूप में हम अपने युवाओं से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हर बार व्यवस्था की नाकामियों को सहते रहें और फिर भी देशभक्ति और राष्ट्र-निर्माण के नारे लगाते रहें। यदि भारत को वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति बनना है, तो उसे सबसे पहले अपने परीक्षा सिस्टम को लीक-प्रूफ और पारदर्शी बनाना होगा। युवाओं का व्यवस्था पर से भरोसा उठना किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सरकार को अब लीपापोती बंद करके परीक्षा तंत्र की इस सड़न को जड़ से खत्म करना होगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि देश के भविष्य और उसकी मानसिक सेहत को बचाने की है।

साप्ताहिक जलसा
स्वयंसिद्धा

छत्तीसगढ़ की अग्रणी महिला संस्था स्वयंसिद्धा-ए मिशन विद ए विजन द्वारा गत 7 वर्षों से प्रत्येक सप्ताह संगीत, साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य, सिनेमा, फोटोग्राफी, कानूनी सलाह आदि समसामयिक विषयों पर नियमित स्तंभ चलाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक मंगलवार परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।

अधिकारियों, जिम्मेदारों, नेताओं, मंत्रियों के विचार तो हम हमेशा सुनते हैं लेकिन आम गृहणियां और माताएं समसामयिक विषयों पर क्या सोचती है इस पर हमने कभी बात नहीं की।

हम समाज में रहते हैं जंगल में नहीं, ओटीटी पर सेंसरशिप शीघ्र लागू हो

संस्था की अध्यक्ष डॉ. सोनाली चक्रवर्ती ने परिचर्चा का शुभारंभ किया कुछ जानकारियों से -"भारत में फिल्मों की सेंसरशिप की शुरुआत सन-1918 में सिनेमैटोग्राफ एक्ट (Cinematograph Act) के लागू होने के साथ हुई थी। शुरुआती सेंसर बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से उन दृश्यों को हटाने के लिए किया जाता था जो ब्रिटिश या यूरोपियों की छवि को नुकसान पहुँचाते थे। साथ ही, अश्लील या आपत्तिजनक' प्रस्तुतियों से जनता को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था।

1 जून 1983 तक इसे 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर' के नाम से जाना जाता था। 1983 में नियमों में संशोधन के बाद इसका नाम बदलकर 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' कर दिया गया। इसका मुख्य कार्य सिनेमाघरों और टेलीविजन पर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होने वाली फिल्में समाज के नैतिक मूल्यों, शिष्टाचार और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान न पहुँचाएँ। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं रखा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ओटीटी एक पर्सनल या ऑन-डिमांड माध्यम है, जहाँ दर्शक अपनी पसंद और उम्र के अनुसार कंटेंट का चुनाव करते हैं।

अपनी पसंद के कंटेंट का अर्थ यह नहीं होता कि हर तरह की अश्लील, हिंसक, आपत्तिजनक दृश्य हमारे घरों के अंदर घुस आए इसीलिए हमने लगातार पीएमओ से चिट्ठी पत्री जारी रखी है कि ओटीटी पर सेंसरशिप शीघ्र लागू हो क्योंकि हम समाज में रहते हैं जंगल में नहीं। समाज के कुछ नियम होते हैं उन नियमों को प्रत्येक जगह लागू करना चाहिए। हमारे पत्र और अभियान की कारण 25 प्लेटफार्म को प्रतिबंधित किया गया है लेकिन अभी भी जो ज्यादा प्रभावशाली ओटीटी है वह धड़ल्ले से चल रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी

भोपाल निवासी अनुभा दीक्षित कहतीं है-"मनोरंजन के अनेक अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार इनमें दिखाई जाने वाली अत्यधिक हिंसा, अश्लील दृश्य, अभद्र भाषा और बिना किसी संवेदनशीलता के प्रस्तुत किए गए विषय चिंता का कारण बनते हैं। बच्चों और किशोरों का मन बहुत प्रभावशील होता है, इसलिए वे जो देखते हैं, उसका असर उनके व्यवहार, सोच और भाषा पर पड़ सकता है।

पूर्ण प्रतिबंध न सही अनावश्यक गालियों, व्यक्तिगत अपमान और सामाजिक मर्यादाओं की अनदेखी को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक माँ के रूप में मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों के संस्कार, उनकी संवेदनशीलता और उनके मानसिक विकास को लेकर है। तकनीक और आधुनिकता का स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आवश्यक है। इसलिए OTT प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल माध्यमों पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखे।

सेक्टर-1 भिलाई निवासी गृहणी गीता चौधरी कहती हैं - "हमारे सेंसर बोर्ड को सख्त होना चाहिए क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार तो देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर रोकते है परंतु आज कल मंनोरज के लिए बच्चे बड़े टीवी या मोबाइल पर दिखाए जा रहे ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखाई जा रहे कंटेट और अश्लील हिंसक दृश्य इतना अधिक बढते जा रहा है कि बच्चों को यह सामान्य लगने लगा है |हर मां बेटी बहन इन पर सेंसरशिप की मांग करती है।

भोपाल निवासी शिक्षिका एवं महिला उद्यमी अनुश्री सरकार कहती हैं -" OTT प्लेटफार्म पर सेंसर लगाना ही चाहिए क्योंकि बच्चे ये सब देखकर बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे youtube खोले या गुगल, instagram या FB सभी में ऐसे जघन्य भद्दी चीजे, गाने, गाली जैसे शब्द आते रहते है। मैं एक माँ के साथ एक टीचर भी हूँ |बच्चों में अक्सर बदलाव देखती रहती हूं, वही सब बाते जब बच्चे बोलते है तो पता चल ही जाता है कि वो न तो उनकी भाषा है ना घर के लोगो की वो होती है सोशल मीडिया यानी OTT प्लेटफार्म के। जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, साइकिल चलाना उन्हें छोड़ कर आज कल बच्चे screentime को ज्यादा दे रहे हैं। साइकोलॉजिकल तौर पर भी बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है |मैं एक स्पेशल बच्चों के स्कूल में हूं, जो बच्चे adolence की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनमें ऐसे कई हामीनल चेंजेस होते है, और ये सब देख कर सुनकर ये बच्चे उन्हें दोहराते है ,इन सब चीजों से कई तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे है।

नेहरू नगर निवासी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की माँ स्मिता चौहान कहती हैं-" यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम कितनी चर्चा कर ले पर दो पहलू सामने आते हैं। पहले नैतिक मूल्यों पर समाज व बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म, सीरियल, मूवी, स्टैंड अप कॉमेडी सभी जगह कूल और हिट बनने के लिए ऐसे कंटेंट बनाए जाते हैं।

इनके कारण बच्चों पर बहुत अधिक और समाज पर बुरा असर हो रहा है इंटरनेट की आसान पहुंच के कारण कम उम्र के बच्चे भी इस तरह के कंटेंट देख लेते हैं जिससे उनके ऊपर बुरा असर होता है। मेरे बेटे के स्कूल के साथियों की पेरेंट्स की मीटिंग चल रही थी। उसमें एक पिता ने अपने बच्चों को माइक ऑन करके ही गालियां देना शुरू किया। जब दूसरे माता-पिताओं ने आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मतलब और अपना माइक ऑफ कर दिया। यह स्थिति चिंताजनक है शुरुआत घर से करनी होगी"

सुरेंद्रनगर गुजरात निवासी लेखिका अर्चना सिंह कहती हैं-"सुरेंद्रनगर गुजरात निवासी लेखिका अचर्ना सिंह कहती है -"एक मां और सबसे पहले एक औरत होने के नाते मुझे ये लगता है कि जो चीज मनोरंजन के लिए बनी थी वो अब बेहद गलत दिशा में मुड़ गया है।अब मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता, संस्कार के नाम पर मजाक किया जा रहा है। सबसे गलत तो ये हो रहा है कि ये सारी चीजें वो देख रहे हैं जिन्हें अभी अपनी जिंदगी शुरू करनी हैं, जो देश के नींव हैं, वो भला क्या सीख रहे हैं। कॉमेडी के नाम पर दूसरों की बेइज्जती करना, गलत भाषा का प्रयोग, जो कि जाहिर है उसका केंद्र बिंदु औरत ही होगी यही हो रहा है।

कभी एक समय हुआ करता था जब दूरदर्शन था जिसमें साहित्यिक धारावाहिक भी दिखलाया जाता था, पर अफसोस अब साहित्य तो कहीं दूर की ही बात हो चुकी है। साथ में जो इस तरह की चीजें बना रहे हैं और जो काम उनमें कर रहे हैं उन्हें भी "सिर्फ पैसों" से इतर अपने सामाजिक दायित्व को समझना चाहिए, क्योंकि वे "हीरो"समझे जाते हैं हैं दशर्कों द्वारा पर अफसोस वे विलेन जैसा काम कर रहे हैं।

वाशी नवी मुंबई निवासी असावरी पराँजपे कहती हैं -"मेरा पोता 3 साल का है। उसके साथ टीवी पर क्या देखें समझ में नहीं आता खराब भाषा और मारधाड़ वाले दृश्य दिखाने का मन नहीं करता है। कॉमेडी भी इतनी सस्ती और निम्न स्तरीय हो गई कि हम ही नहीं सुन सकते |सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं आता है |ओटीटी पर शीघ्र लगाम लगनी चाहिए।

शिक्षाविद डॉ. सुचित्रा शर्मा कहती है-"मां" केवल एक शब्द नहीं, बल्कि त्याग, ममता, करुणा, अनुशासन, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का साकार रूप है। ईश्वर ने स्त्री के भीतर जिन श्रेष्ठ गुणों को समाहित किया है, उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति मातृत्व में दिखाई देती है। एक मां अपने परिवार का पालन-पोषण कर बच्चों को सही और गलत का भेद सिखाती है, उनके व्यक्तित्व को आकार दे उन्हें एक सार्थक जीवन-दृष्टि प्रदान करती है। वह अपने संस्कारों, आदर्शों और मूल्यों की मजबूत नींव बच्चों के भीतर स्थापित करती है, ताकि वे एक संवेदनशील, जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बन सकें।

ऐसी स्थिति में जब एक मां समाज में बढ़ती हिंसा, अभद्र भाषा, असंवेदनशील व्यवहार और मनोरंजन के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता को देखती होगी, तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से पीड़ा उत्पन्न होती होगी। उसने तो कभी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, फिर समाज में दिखाई देने वाला यह व्यवहार आखिर कहां से आ रहा है? यह भी विचारणीय है कि जो लोग आज समाज में इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, वे भी कभी किसी मां की गोद में पले-बढ़े बच्चे ही थे।

आने वाली पीढ़ियों को केवल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों से समृद्ध बनाना ही हमारी सबसे बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी है।

इनके अलावा

क़ुदसिया अली, देबजानी मजूमदार, स्मिता मंडल, प्रिंयका सिंह, सीमा लदेर, आरती तिवारी, अचर्ना सिंह, राजश्री नायर, नमिता त्रिपाठी, लक्ष्मी साहू, संध्या तिवारी, संगीता जयसवाल, रीता वैष्णव, पुनीता कौशल, कमलेश आर्य ने भी बेहद प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी एवं सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की।

तालपुरी निवासी पुनीता कौशल कहती हैं-" आजकल ओटीटी प्लेटफार्म पर जो परोसा जा रहा है वो कोई भी माता पिता हजम नहीं कर पा रहे है |ये एक गंभीर विषय है। सिर्फ.पैसा कमाने, ,"ार बटोरने के लिए कुछ भी दिखाया जा रहा है |उसमे अश्लील संवाद दोहरी मानसिकता को तो दर्शाता है |फूहड़ नृत्य गानों के बोल ऐसे भी है जो अगर सुनकर किसी की जुबान पर आ जाए तो सुनकर घृणा आए |क्राइम को इतने डिटेल में बताया जाता है कि बस यही सीखना बाकी हो जैसे।

मर्यादा को लांघने वाले ये जाने माने प्लेटफॉर्म है जिन्हें अमूमन हर घर की टीवी पर या मोबाइल पर चलाया जा रहा है बिना किसी रोकटोक के। सेंसर बोर्ड कृपया अच्छे से देखकर कोई भी सीरीज, रील या कॉमेडी शो को पास करें जिससे घर में बैठ के बच्चे बड़े भी एक साथ देख सके । कुछ मर्यादा हो भाषा की गरिमा रखी जाए |टीवी पर पैरेंटल गाइडिंग के लिए ऑप्शन है, बहुत कम है जो उन्हें इस्तेमाल करते है ।

अलग-अलग नाम से अपना प्रोफाइल बनाया जाता है एक ही अकाउंट में जिसका नाम का है वही खोले और यदि किसी बच्चे ने कुछ सर्च किया तो दिख जाता है । चाइल्ड लॉक की भी सुविधा है । हमेशा 13+,16+,18+ सेंसर बोर्ड के नियमानुसार लिखा जाता है चाहे वेब सीरीज हो या फि ल्म लेकिन..क्या पैरेंट्स इतने जागरूक है? कि बच्चे क्या देख रहे है |मोबाइल में स्क्रीन टाइम और क्या सर्च किया हिस्ट्री में देखा जा सकता है लेकिन बहुत कम मातापिता ये करते है।

सेक्टर 8 निवासी कलाकार लक्ष्मी साहू कहती हैं-" माँ न सिर्फ जन्म और पोषण देती है बल्कि शिशु को पोषण के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सनातन में उल्लेखित श्रेष्ठ गुणों का भी पोषित करती हैं लेकिन आज वैश्विक संचार की दुनिया में मानवीय गुणों एवं मूल्यों का वैश्विक संचार में कमी देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण आज माताओं को अपने अपने बच्चों में विकसित हो रहे नैतिक एवं चारित्रिक पतन के कारण गहरी चिंता लगी है। आज भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए डळळ प्लेटफॉर्म पर सस्कृति एवं नैतिक हास करने वाले संदर्भ प्रस्तुत किए जाते है जिसे देखने के कारण से भारत की युवा पीढ़ीयो में भी नैतिक सामाजिक एवं साँस्कृतिक पतन देखने को लगातार मिल रही है।

ऐसी पीढ़ियां न तो सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है न ही समृद्ध एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। उपरोक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के लिये हमें संयुक्त रूप से देश की सरकार पर सामुहिक दबाव देना चाहिए तथा अपने राष्ट्र के लिए अलग से सर्च इंजन बनाने के लिये मांग करना चाहिए। अभी अभी सरकार ने स्वदेशी सर्च इंजन लांच किया है। ऐसे प्लेटफॉर्म को अपनाकर एवं बढ़ावा देकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत हद तक सेंसर कर सकते है। हर माँ को चाहिए कि अपने संचार माध्यमों में स्वदेशी सर्च इंजन का उपयोग करें एवं डळळ सेंसर से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराये।

खास खबर

सक्ती में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सीईओ सहित तीन लोग रिश्वत लेते गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत सक्ती के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित तीन लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत सक्ती के सीईओ निखिल कश्यप, सहायक ग्रेड-3 अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु पर एक हितग्राही का भुगतान जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया था कि लगभग 12 लाख रुपये का भुगतान संबंधी चेक जारी करने के लिए अधिकारियों द्वारा 2 लाख रुपये कमीशन की मांग की जा रही है।

मामले की शिकायत मिलने के बाद एसीबी बिलासपुर की टीम ने इसकी गोपनीय जांच और सत्यापन किया। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर अधिकारियों ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। तय रणनीति के तहत शिकायतकर्ता को आरोपियों के संपर्क में रखा गया और रिश्वत की रकम देने की प्रक्रिया पर नजर रखी गई। बताया जा रहा है कि ट्रैप के दौरान आरोपियों को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद एसीबी की टीम ने जनपद पंचायत कार्यालय सक्ती में दबिश दी और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

एसीबी अधिकारियों ने मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है और रिश्वतखोरी का यह मामला कितने समय से चल रहा था। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि हितग्राही का भुगतान जारी करने और चेक देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत देने से इनकार किए जाने के बाद उसने मामले की जानकारी एसीबी को दी, जिसके बाद पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

फिलहाल एसीबी की टीम तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच के आधार पर आगे और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद सक्ती जिले के प्रशासनिक अमले में हलचल बढ़ गई है। सरकारी कार्यालयों में भी इस मामले की चर्चा हो रही है। एसीबी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी या भ्रष्ट आचरण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी सरकारी कार्यालय में उनसे रिश्वत की मांग की जाती है तो वे इसकी जानकारी तुरंत संबंधित एजेंसियों को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

राजनांदगांव पुलिस ने शुरू किया अभिनव पहल पहल, डॉ. रमन सिंह ने किया शुभारंभ

2600 लोगों की मौजूदगी में रीडिंग रूम, नि :शुल्क कोचिंग और मेंटरशिप कार्यक्रम लॉन्च

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

पुलिस और समाज के बीच विश्वास व संवाद बढ़ाने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के नेतृत्व में जन-केंद्रित अभियान पहल की शुरुआत की। 15 जून को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह मुख्य अतिथि रहे। सांसद संतोष पांडेय, जिले के विधायक, महापौर मधुसूदन यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

2600 लोगों ने लिया हिस्सा

कार्यक्रम में 550 कोटवार, करीब 1000 ग्रामवासी, 400 प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी, 500 से अधिक यातायात मित्र और 111 गुड समैरिटन्स समेत लगभग 2600 लोगों ने भाग लिया।

पहल रीडिंग रूम का शुभारंभ

झुग्गी बस्तियों, अटल आवास कॉलोनियों और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए पहल रीडिंग रूम शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार एक कमरे में रहने वाले परिवारों और घरेलू समस्याओं के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता। रीडिंग रूम उन्हें शांत और सुरक्षित अध्ययन स्थल देगा। सबसे अधिक मांग चिखली थाना क्षेत्र से आई, जो अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है।

111 गुड समैरिटन्स का सम्मान

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद कर जीवन बचाने वाले 111 गुड समैरिटन्स को सम्मानित किया गया। 500 से अधिक यातायात मित्र भी शामिल हुए जो गोल्डन ऑवर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करते हैं।

नई पहलें : नि :शुल्क कोचिंग और मेंटरशिप

1. पहल नि:शुल्क कोचिंग: पुलिस लाइन में रोज सुबह 7 से 10 बजे तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। नए उप निरीक्षक और विषय विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे।

2. पहल मेंटरशिप कार्यक्रम: थानों में पदस्थ अधिकारी विद्यार्थियों के मेंटर बनेंगे और उन्हें मार्गदर्शन देंगे।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कहा कि पहल का उद्देश्य शिक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग को जोड़कर युवाओं को सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बनाना है।

164 अपराधमुक्त गांवों के सम्मान में वृक्षारोपण

2024, 2025 और 2026 में अपराधमुक्त रहे 164 गांवों के सम्मान में पुलिस लाइन और थाना परिसरों में वृक्षारोपण किया गया। ग्रामीण सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए कोटवार सम्मेलन हुआ। अपराधमुक्त गांवों के सरपंचों, पटेलों और प्रतिनिधियों ने अनुभव साझा किए।

विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों का किया विशेष निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण एक सुरक्षा अभियान है, जिसे परिवहन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित वाहनों की फिटनेस जांचना और छात्रों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है।

संयुक्त टीम ने 15 जून से जिले में संचालित स्कूल बसों का करेगी निरीक्षण विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गरियाबंद जिले में स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। यह अभियान सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देशों तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुरूप संचालित किया गया। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला सेनानी कार्यालय की संयुक्त टीम ने 15 जून को जिले में संचालित स्कूल बसों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों और परमिट संबंधी शर्तों की जांच की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में पंजीकृत 75 स्कूल बसों में से 30 बसों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बसों में निर्धारित सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल, आवश्यक उपकरणों तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया। परिवहन विभाग द्वारा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, कर (टैक्स), बीमा, फिटनेस प्रमाण-पत्र और परमिट सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई, ताकि विद्यार्थियों के परिवहन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

चालक-परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल बस चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बच्चों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने वाले कमर्चारी शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन की दी जानकारी जिला सेनानी कार्यालय द्वारा बसों में लगाए गए अग्निशमन यंत्रों की जांच की गई तथा चालक-परिचालकों को इनके उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

अनुपस्थित बस संचालकों पर कार्रवाई निरीक्षण के दौरान 45 स्कूल बसें उपस्थित नहीं मिलीं। इस पर संबंधित स्कूल बस संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ में आज से बंद हुए सभी टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य, एक अक्टूबर तक जंगल सफारी पर रोक

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मानसून के आगमन और वन्यजीवों के प्रजनन काल को देखते हुए, हर साल की तरह इस वर्ष भी देश के अधिकांश टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जंगल सफारी 15 जून से 1 अक्टूबर तक साढ़े 3 महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है ।पीसीसीएफ एवं वन बल प्रमुख अरुण पांडेय ने बताया, हर साल मानसून के पहले टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को बंद कर दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ में प्रकृति और वन्यजीवों की सुरक्षा तथा उनके प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) और वन्यजीव अभयारण्यों को आज (15 जून) से पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मानसून के आगमन के साथ ही जंगलों में पर्यटन गतिविधियों पर यह अस्थायी रोक आगामी 1 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद वन्यप्राणी सप्ताह के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 से जंगल सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियां दोबारा शुरू की जाएंगी।

वन विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार, इस रोक के पीछे दो मुख्य कारण हैं। वर्षा ऋृतु के दौरान जंगलों के भीतर स्थित कच्चे मार्ग और सफारी ट्रैक बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। लगातार बारिश से नदी-नालों में उफान और रास्तों में जलभराव के कारण आवागमन बेहद कठिन और जोखिम भरा हो जाता है। मानसून का समय वन्यप्राणियों के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। यह अवधि अधिकांश वन्य प्रजातियों के प्रजनन और उनके शावकों के पालन-पोषण का समय होती है। इस दौरान इंसानी दखल को रोककर वन्यजीवों को एक शांत और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है।

ये प्रमुख पर्यटन स्थल रहेंगे बंद

अगले साढ़े तीन महीनों के लिए प्रदेश के इन प्रमुख संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जिनमें अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, प्रदेश के अन्य सभी अधिसूचित अभयारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं।

बंद के दौरान वन विभाग चलाएगा विशेष अभियान

पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद रहने के दौरान वन विभाग शांत बैठेने के बजाय जंगलों के भीतर कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित करेगा। अवैध शिकार को रोकने के लिए गश्त तेज की जाएगी और वन्यजीवों की क्लोज मॉनिटरिंग होगी। जंगलों के भीतर प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। आगामी पर्यटन सत्र को ध्यान में रखते हुए सफारी मार्गों, ट्रैकों और रिसॉर्ट्स की मरम्मत व रखरखाव किया जाएगा, ताकि 2 अक्टूबर से पर्यटकों को बेहतर और सुरक्षित अनुभव मिल सके।

वन्यजीव संरक्षण हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता

वन विभाग का कहना है कि वन्यजीव संरक्षण हमेशा सवीच्च प्राथमिकता है। हर साल हजारों पर्यटक छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों का भ्रमण करते हैं, लेकिन मानसून ब्रेक इस अनुभव को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और सतत पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भले ही यह कुछ महीनों का इंतजार है, लेकिन पारिस्थितिकी संतुलन और वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से मानसून का यह ग्रीन ब्रेक बेहद जरूरी और सराहनीय कदम माना जा रहा है। आगामी 2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के जंगल एक बार फिर नए रोमांच के साथ सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार होंगे।

'ऑब्सेस' में खुद किए सभी स्टंट, इसमें ग्लैमर कम और अभिनय की गुंजाइश ज्यादा थी

एक्ट्रेस ईशा सिंह की फिल्म 'ऑब्सेस' 29 मई को रिलीज हुई। इसे लेकर उन्होंने खास बातचीत की...

'ऑब्सेस' के रिलीज तक पहुंचने पर कैसा महसूस हो रहा है?

अभी तक हम फिल्म की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि सफर के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि हम बहुत दूर आ गए हैं। एक छोटे शहर से निकलकर यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूं। इससे पहले मैंने 'मिडिल क्लास लव' की थी, जो एक रोमांटिक फिल्म थी। 'ऑब्सेस' पूरी तरह अलग है। जब मुझे कहानी सुनाई गई तो लगा कि यह कुछ नया और चुनौतीपूर्ण है। इसमें ग्लैमर कम और अभिनय की गुंजाइश ज्यादा थी। इसलिए मैंने तुरंत हां कह दी।

ऑब्सेशन का मतलब आपके लिए क्या है। जिंदगी में किस तरह शामिल है?

मैं अपने काम को लेकर ऑब्सेस्ड हूं। मेरा मानना है कि मेहनत करते रहो और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। समय हर सवाल का जवाब देता है। इससे ज्यादा क्या कहूं।

छोटे शहरों के एक्टर्स को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है?

आज भी कई लोगों को लगता है कि एक्टिंग कोई करियर नहीं है। खासकर लड़कियों को बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे फैंस ने भी हमेशा मेरा साथ दिया है। वे मेरे लिए पोस्टर बनाते हैं, ट्रेंड चलाते हैं और हर मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूं।

फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई यादगार या जोखिम भरा अनुभव ?

फिल्म में मैंने खुद ड्राइविंग और कई स्टंट किए हैं। एक बार शूटिंग के दौरान कार का बैलेंस बिगड़ गया था और बड़ा हादसा होते-होते बचा। उस समय मैं बहुत डर गई थी। हमने ज्यादातर स्टंट्स रियल लोकेशन्स पर शूट किए।

ओटीटी से वापसी करेंगी कटरीना कैफ

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कटरीना कैफ मां बनने के बाद एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं। कटरीना अब सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि अब वह ओटीटी पर भी हाथ आजमाने की सोच रही हैं।

ओटीटी से कर सकती हैं वापसी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कटरीना ने नई कहानियों की स्क्रिप्ट्स को पढ़ना और उनका चुनाव करना शुरू कर दिया है। वह काफी सोच-समझकर अपने अगले प्रोजेक्ट का फैसला लेंगी। कटरीना 2027 के आखिरी महीनों तक अपनी अगली फिल्म या प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर सकती हैं। वे किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहती हैं।

ओटीटी पर नजर

कटरीना पहली बार किसी वेब सीरीज या डिजिटल प्रोजेक्ट में काम करने की इच्छा जता रही हैं, क्योंकि आज के समय में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कलाकारों को बेहतरीन मौके दे रहे हैं। एक मां बनने के बाद, कटरीना अब ऐसी भूमिकाएं तलाश रही हैं जो उनके निजी जीवन और काम, दोनों के साथ तालमेल बिठा सकें।

बड़े पर्दे से दूरी

कटरीना कैफ को आखिरी बार साल 2024 में फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में विजय सेतुपति के साथ देखा गया था। तब से वे लाइमलाइट और मीडिया से थोड़ा दूर थीं। कटरीना ने साल 2021 में एक्टर विक्की कौशल से शादी की थी। उन्हें 'वेलकम', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' और 'एक था टाइगर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनके फैंस अब बड़े पर्दे या ओटीटी पर उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

रोमांस-थ्रिलर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हैं कीर्ति

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कीर्ति सुरेश के अगले प्रोजेक्ट को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक बड़े बजट की रोमांस-थ्रिलर फिल्म के लिए बातचीत कर रही हैं। हालांकि, फिल्म को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार, कीर्ति एक प्रमुख फिल्मकार की नई फिल्म से जुड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसमें कीर्ति को ऐसे जॉनर में देखने का मौका मिल सकता है, जिसमें उन्होंने अब तक बहुत ही कम काम किया है। कीर्ति सुरेश पिछले कुछ वर्षों में तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में लगातार सक्रिय रही हैं। उन्होंने व्यावसायिक फिल्मों के साथ-साथ अभिनय प्रधान भूमिकाओं में भी अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में रोमांस और थ्रिलर के मिश्रण वाली कहानी में उनका चयन दिलचस्प माना जा रहा है।

फिर विभाजन की त्रासदी दिखाएंगे सनी देओल, सामने आई फिल्म 'बंटवारा 1947' की पहली झलक

सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म का दर्शकों के बीच गजब का उत्साह है। जब से इस फिल्म का एलान हुआ है, तब से इससे जुड़ी हर अपडेट पर नजर है। पहले इसे 'लाहौर 1947' कहा जा रहा था। मगर, फिल्म का आधिकारिक टाइटल 'बंटवारा 1947' है।

आजादी के पर्व पर रिलीज होगी फिल्म

फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया गया है। यह फिल्म इस साल आजादी के पर्व पर रिलीज होगी। आमिर खान प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया है। पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'नफरत और डर के माहौल में, उन्होंने हिम्मत का रास्ता चुना। 14 अगस्त 2026 से सिनेमाघरों में 'बंटवारा' देखें'।

मशाल थामे नजर आए सनी देओल

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिल्म सिनेमाघरों में सजेगी। यह फिल्म भी इसी विषय पर आधारित है। इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी देखने को मिलेगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म इमोशंस से भरपूर होगी। फिल्म की रिलीज डेट का एलान मेकर्स ने टीजर के साथ किया है। यह काफी मार्मिक है। सनी देओल हाथों में मशाल थामे नजर आ रहे हैं। प्रीति जिंटा और अन्य कलाकार भी हैं। सभी के चेहरों पर एक दहशत नजर आ रही है। टीजर यह समझने के लिए काफी है कि बंटवारे की आंच में जिंदगियां किस कदर झुलसी थीं।

दर्शक हुए उत्साहित दी ऐसी प्रतिक्रिया

इस फिल्म के निर्देशन और स्क्रीनप्ले की जिम्मेदारी राजकुमार संतोषी के कंधों पर है। वहीं, फिल्म का निर्माण आमिर खान कर रहे हैं। फिल्म की पहली झलक देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूजर्स लिख रहे हैं कि क्या ही शानदार कॉम्बो है।

सुभाष घई ने 'ताल' के सीक्वल को लेकर दिया संकेत

बॉलीवुड निर्देशक सुभाष घई की मशहूर फिल्म 'ताल' आज भी लोगों को बहुत पसंद है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। सुभाष घई इस सुपरहिट रोमांटिक फिल्म का दूसरा भाग यानी 'ताल 2' बनाने की सोच रहे हैं। सुभाई ने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि क्या वह नए कलाकारों के साथ 'ताल 2' देखना चाहेंगे?

सुभाष घई का पोस्ट

सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर ताल का एक पोस्टर हाथ में पकड़े हुए तस्वीर शेयर की है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि फिल्म की तारीफ रोजर एबर्ट ने की थी। इसी के साथ उन्होंने प्रशंसकों से पूछा कि क्या उन्हें इसे नए कलाकारों और निर्देशक के साथ 'ताल 2' बनानी चाहिए।

फिल्म को मिली तारीफ

अपनी पोस्ट में सुभाष घई ने यह भी बताया कि उन्हें इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी तारीफ किससे मिली थी। साल 2005 में शिकागो के 'एबर्टफेस्ट' में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हॉलीवुड के मशहूर फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने फिल्म 'ताल' की तारीफ की थी। रोजर एबर्ट ने 'ताल' को 'शुद्ध मनोरंजन' और 'मासूमियत से भरी' फिल्म बताया था। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में हॉलीवुड के पुराने दौर के क्लासिक संगीत जैसा जादू है, जो अब अमेरिकी फिल्मों से गायब हो चुका है। वह फिल्म के गानों, डांस और ऐश्वर्या राय की एक्टिंग से बहुत प्रभावित हुए थे।

कब रिलीज हुई थी 'ताल'

फिल्म 'ताल' 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई है। अमरीश पुरी और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में दिखें। इस फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने दिया था, जिसके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं।

कृति खरबंदा, अपनी पीढ़ी की सबसे अंडररेटेड अभिनेत्रियों में से क्यों हैं?

जिस इंडस्ट्री में, अक्सर शोर, सुर्खियों और दिखावे को सफलता का पैमाना माना जाता है, वहां कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जो बिना ज्यादा प्रचार के अपनी निरंतरता, बहुमुखी प्रतिभा और अपने काम के प्रति समर्पण के दम पर मजबूत करियर बनाते हैं और कृति खरबंदा इसी श्रेणी की अभिनेत्री हैं। वर्षों से कृति ने हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में सफलतापूर्वक काम करते हुए अलग-अलग इंडस्ट्री, जॉनर और दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई है।

अपनी मजबूत फिल्मोग्राफी के बावजूद उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों की चर्चा में वह जगह नहीं मिली, जिसकी वे हकदार रही हैं। शायद यही वजह है कि 'राणा नायडू 2' में उनकी परफॉर्मेंस, सीरीज की रिलीज के एक साल बाद भी, चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

गौरतलब है कि आलिया ओबेरॉय के किरदार में कृति ने भारत की सबसे चर्चित स्ट्रीमिंग फ्रेंचाइजी में कदम रखा और अपने साथ एक ताजगी भरी ऊर्जा लेकर आईं। यह किरदार उन भूमिकाओं से काफी अलग था, जिनसे दर्शक अब तक उन्हें जोड़ते आए थे। हालांकि महत्वाकांक्षा, भावनात्मक जटिलताओं, संवेदनशीलता और मजबूती से पिरोए गए इस किरदार को निभाना उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन इसे उन्होंने एक चुनौती की तरह लिया और सच कर दिखाया।

सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने दमदार व्यक्तित्वों और प्रभावशाली परफॉर्मेंस से भरी कहानी में भी अपनी अलग मौजूदगी बनाए रखी। जहां शो में हाई-स्टेक ड्रामा और बड़े किरदारों का दबदबा था, वहीं कृति की परफॉर्मेंस कभी भी दबती हुई महसूस नहीं हुई। उन्होंने संयम और आत्मविश्वास के साथ अपने किरदार को निभाते हुए यह साबित किया कि प्रभाव छोड़ने के लिए हमेशा ऊंची आवाज़ या अत्यधिक नाटकीयता की जरूरत नहीं होती।

'राणा नायडू 2' ने कृति की उस खासियत को भी सामने लाया, जो शुरुआत से उनकी पहचान रही है, और वह थी खुद को हर परिस्थिति और किरदार के अनुसार ढाल लेने की क्षमता। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो इतनी सहजता से भाषाओं, जॉनर और फॉर्मेट्स के बीच बदलाव कर पाते हैं। रोमांटिक एंटरटेनर्स और कॉमेडी फिल्मों से लेकर थ्रिलर्स और अब एक रॉ और ग्रिटी स्ट्रीमिंग ड्रामा तक, कृति ने लगातार खुद को नए रूप में पेश किया है, बिना अपनी सच्चाई और सहजता खोए। शायद यही कारण है कि कृति आज भी इंडस्ट्री की सबसे अंडररेटेड परफॉर्मर्स में से एक मानी जाती हैं।

उन्होंने कभी किसी एक इमेज या तय फॉर्मूले पर निर्भर रहने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने चुपचाप एक विविधतापूर्ण फिल्मोग्राफी तैयार की, जहां हर किरदार खुद उनके काम की गवाही देता है। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव ने दर्शकों को पारंपरिक लेबल्स से आगे बढ़कर कलाकारों को नए नजरिए से देखने का अवसर दिया है, और इसी के साथ 'राणा नायडू 2' ने एक बार फिर कृति की रेंज और स्क्रीन प्रेजेंस की याद दिलाई। इसने एक ऐसी अभिनेत्री को सामने रखा, जो जोखिम लेने से नहीं डरती, चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को अपनाती है और मनोरंजन जगत के बदलते दौर के साथ लगातार खुद को विकसित करती रहती है।

यही वजह है कि एक साल बाद भी 'राणा नायडू 2', कृति खरबंदा के करियर का एक अहम पड़ाव बना हुआ है, इसलिए नहीं कि इसने उन्हें दर्शकों से परिचित कराया, बल्कि इसलिए कि इसने सभी को फिर याद दिलाया कि वह क्या करने में सक्षम हैं। और अगर उनके हालिया प्रोजेक्ट्स कोई संकेत देते हैं, तो संभव है कि उनके करियर के सबसे बेहतरीन अध्याय अभी बाकी हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से बढ़ा जनविश्वास : शिकायतों के त्वरित निराकरण से लोगों को मिल रही राहत

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा के संकल्प को साकार करने में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेशभर में एक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित हो रही है। बेमेतरा जिले में भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकों के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि अब उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है तथा समय पर समाधान मिलने से शासन और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन मे जिले मे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से आम नागरिक बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और संबंधित विभागों द्वारा उन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। शासन की इस पहल ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह, पारदर्शी तथा जनोन्मुखी बनाया है।

शिकायतों के निराकरण में जिले का बेहतर प्रदर्शन

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बेमेतरा जिले में कुल 369 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से 79 शिकायतों का संतोषजनक निराकरण किया जा चुका है तथा 286 शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। 4 शिकायतें नियमानुसार निरस्त की गई हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि आगामी तीन दिनों में समय-सीमा से बाहर होने वाली शिकायतों की संख्या शून्य है तथा निर्धारित समय-सीमा से बाहर लंबित शिकायतें भी नहीं हैं। यह स्थिति प्रशासन की सतत निगरानी एवं नियमित समीक्षा का परिणाम मानी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज प्रत्येक शिकायत का गंभीरतापूर्वक परीक्षण करते हुए निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलंब न हो।

जनता को मिल रहा त्वरित लाभ, बढ़ रहा भरोसा

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा उसका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है तथा शिकायतकर्ता को पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व्यवस्था को जनहितकारी बताते हुए कहा है कि इससे प्रशासन तक उनकी पहुंच आसान हुई है। लोगों को यह विश्वास मिला है कि उनकी बात सुनी जा रही है और समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रति नागरिकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

प्रमुख विषयों से जुड़ी हैं शिकायतें

जिले में प्राप्त शिकायतों में अतिक्रमण संबंधी मामले प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित विद्युत आपूर्ति एवं ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्याएं, विभिन्न कृषि योजनाओं के अंतर्गत अनुदान एवं सहायता राशि के भुगतान में विलंब, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पात्रता संबंधी शिकायतें तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नए गैस कनेक्शन से संबंधित आवेदन प्रमुख रूप से सामने आए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप अनेक शिकायतों का निराकरण कर हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शासन और जनता के बीच संवाद का एक मजबूत सेतु भी बन रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है तथा विभागीय जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश में सुशासन को मजबूत करने और आम नागरिकों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उसी सोच का परिणाम है, जिसके माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है।

बेमेतरा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सवोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कर शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है ताकि नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके। जिला प्रशासन का मानना है कि शासन की योजनाओं और सेवाओं का वास्तविक लाभ तभी संभव है, जब लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर हो। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का मूल उद्देश्य आम जनता को सरल, सुलभ और पारदर्शी शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराना था। बेमेतरा जिले में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, नागरिकों की बढ़ती संतुष्टि और शासन के प्रति बढ़ते विश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान, प्रशासन की सक्रियता और शासन की जनकल्याणकारी सोच मिलकर सुशासन के उस मॉडल को मजबूत कर रही है, जिसकी परिकल्पना मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के लिए की है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनसमस्याओं के समाधान का यह अभियान आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है तथा

खास खबर

रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन मामले में हाईवा जब्त

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन राजनांदगांव द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में डोंगरगढ़ क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर राजस्व एवं खनिज विभाग की टीम ने एक हाईवा जब्त किया।

कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर की गई कार्रवाई में हाईवा क्रमांक सीजी 08 बीसी 9633 को जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना डोंगरगढ़ के सुपुर्द कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

गीला, सूखा, सेनेटरी और विशेष कचरे को अलग करने ग्रामीणों को किया जा रहा प्रेरित - सीईओ अग्रवाल

471 ग्राम पंचायतों में चल रहा विशेष जनजागरण कार्यक्रम

कवर्धा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनजागरूकता के उद्देश्य से जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा जिले की 471 ग्राम पंचायतों में व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में ग्रामीणों को कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं पृथक्करण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत स्वच्छता दीदियों द्वारा घर-घर पहुंचकर ट्राइसाइकिल के माध्यम से गीला, सूखा, सेनेटरी तथा विशेष कचरे को अलग-अलग संग्रहित करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही प्लास्टिक के उपयोग को कम करने तथा उसके पुर्नचक्रण (रीसाइक्लिंग) के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नारा लेखन, चित्रकला, चैपाल, रैली, वाडर्वार बैठक एवं घर-घर संपर्क जैसे विभिन्न माध्यमों से लोगों को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता ग्राही ग्रामीणों को खुले में कचरा नहीं फेंकने, प्लास्टिक नहीं जलाने तथा प्लास्टिक कचरे को नालियों, तालाबों एवं नदियों में नहीं डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में रखे तथा उसका उचित स्थान पर निपटान सुनिश्चित करे। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ गांवों के निर्माण में भी मदद मिलेगी।

कचरा संग्रहण होगा आसान

जिला समन्वयक संजय सोनी ने जनपद पंचायत लोहारा के ग्राम पंचायत बिरेंद्रनगर, अचनाकपुर एवं हथलेवा में आयोजित बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत स्वच्छता ग्राही दीदियां एवं पंचायत प्रतिनिधि सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने से उसके संग्रहण, परिवहन एवं निपटान की प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता के बिना इस अभियान की सफलता संभव नहीं है। ग्रामीणों के सहयोग और जागरूकता से ही स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण-अनुकूल गांवों का निर्माण किया जा सकेगा।

सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों को देता था धोखा

राजनांदगांव पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग दीपक कुमार बघेल (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों को धोखा देता था। आरोपी युवकों से दोस्ती करता, फिर लड़की की आवाज में बातचीत कर विश्वास जीतता और पैसों की मांग करता था। पैसे न मिलने पर धमकी, गाली-गलौज और ब्लैकमेलिंग करता था। मामला तब उजागर हुआ जब लालबाग थाना क्षेत्र की एक युवती को आरोपी ने कॉल कर उसके पिता के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने की झूठी जानकारी दी। युवती ने जब इस सूचना को गलत बताया, तो आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया। बाद में युवती के पिता ने संपर्क किया, तो उन्हें भी गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई।

शिकायत मिलने के बाद लालबाग पुलिस और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए आरोपी की पहचान की। जांच में पता चला कि आरोपी की लोकेशन खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र के ग्राम विष्णुपुर में थी। पुलिस ने घेराबंदी कर दीपक कुमार बघेल को गिरफ्तार किया। पूछताछ और तकनीकी जांच में यह भी सामने आया कि दीपक लंबे समय से सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल चला रहा था। वह युवकों को प्रेमजाल और दोस्ती के नाम पर फंसाकर आर्थिक लाभ लेता था। विरोध करने वालों को अश्लील संदेश, धमकी और ब्लैकमेलिंग के जरिए डराता था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साइबर अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच जारी है, जिससे अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान की जाएगी। राजनांदगांव पुलिस ने इस मामले को सोशल मीडिया पर बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति चेतावनी भी बताया। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन पहचान हमेशा वास्तविक नहीं होती। फर्जी प्रोफाइल के पीछे कौन है, इसका अंदाजा लगाना आम लोगों के लिए आसान नहीं है। ऐसे में किसी अज्ञात व्यक्ति से निजी जानकारी साझा करने या आर्थिक लेन-देन करने से पहले पूरी सतकर्ता बरतना जरूरी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सोशल मीडिया पर दोस्ती, प्रेम या नौकरी के बहाने किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा संपर्क करने पर उसकी पहचान जांचना जरूरी है। किसी भी संदिग्ध संदेश, कॉल या आर्थिक मांग पर तुरंत पुलिस या साइबर सुरक्षा टीम को सूचित करना चाहिए। इस गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए साइबर अपराधियों की पहचान कर उन्हें कानून के कटघरे में ला रही है। राजनांदगांव पुलिस ने बताया कि भविष्य में भी साइबर ठगों और ऑनलाइन धोखाधड़ी में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस घटना ने एक बार फिर नागरिकों के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता को उजागर किया है। ऑनलाइन दोस्ती या संपर्क में किसी भी प्रकार की वित्तीय लेनदेन से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल और सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

दोपहिया वाहन से अवैध शराब जब्त

अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए राजनांदगावं जिले मे आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में जिला स्तरीय उड़नदस्ता और आबकारी वृत्त चिचोला की संयुक्त टीम ने ककोड़ी-बंजारी मार्ग पर कार्रवाई करते हुए एक दोपहिया वाहन से 5 .4 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की। आबकारी अधिकारियों के अनुसार बाइक (सीजी 08 एबी 9020) से महाराष्ट्र निर्मित 30 नग देशी शराब संत्री नंबर-01 का परिवहन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान ग्राम कोलिहा लमटी निवासी मुकेश्वर साहू को पकड़ा गया। जब्त शराब और वाहन की कुल अनुमानित कीमत करीब 40 हजार रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 14वां चरण की हुई शुरुआत

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ष्मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियानष के अंतर्गत 14वां चरण दिनांक 15 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य को पूर्णतः मलेरिया मुक्त बनाना तथा वर्ष 2027 तक शून्य स्थानीय मलेरिया प्रकरण प्राप्त करना है। इस दौरान समुदाय स्तर पर मलेरिया परजीवी के समूल उन्मूलन एवं संक्रमण श्रृंखला को समाप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण जांच, उपचार एवं जन-जागरुकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

सीएमएचओ डॉ तूरे ने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं बैठक आयोजित की जा चुकी है तथा मैदानी स्तर पर काययीजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। विकासखंड बोड़ला के 114 ग्रामों में की 58,159 जनसंख्या को कवर करते हुए घर-घर जाकर मलेरिया जांच की जाएगी। इसके लिए 114 सर्वे दल गठित किए गए हैं जिनमें प्रत्येक दल में दो स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं। सर्वे के दौरान प्रत्येक घर में स्टिकर चस्पा किया जाएगा तथा जांच किए गए व्यक्तियों के पैर के अंगूठे के नाखून में नेल मार्किंग की जाएगी, जिससे दोहराव से बचा जा सके और शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित हो।

अभियान के अंतर्गत घर-घर जाकर आरडीटी किट के माध्यम से मलेरिया जांच की जाएगी तथा पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को तत्काल मलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध कराकर पूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। जांच किए गए व्यक्तियों का विवरण आयुष्मान कार्ड नंबर/आभा आईडी नंबर/राशन कार्ड नंबर के आधार पर मोबाइल एनआईसी ऐप में रियल टाइम दर्ज किया जाएगा, जिससे निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनी रहे। साथ ही मच्छरदानी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा तथा लार्वा स्रोत नियंत्रण एवं स्वच्छता गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।अभियान के दौरान जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी तथा साप्ताहिक समीक्षा के माध्यम से प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा।

अभियान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा आवश्यक सामग्री जैसे त्क्ज किट, मलेरिया रोधी दवाएं एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराया गया हैं। मैदानी स्तर पर मितानिन एमटी एवं उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से घर-घर जाकर सर्वे, जांच एवं उपचार कार्य संपादित करेंगे तथा समुदाय को मलेरिया से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करेंगे। जिले में मलेरिया उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले 10 वर्षों में जिले का वार्षिक परजीवी सूचकांक (एपीआई) 10 से घटकर 1 तक पहुंच गया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य एवं राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मलेरिया के प्रमुख लक्षणों में ठंड के साथ बुखार आना सिरदर्द, उल्टी एवं दस्त शामिल हैं। ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराना आवश्यक है।

अवैध उर्वरक भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गाड़ाडीह में 585 बोरी उर्वरक जब्त

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन मे जिले मे खरीफ सीजन 2026 के दौरान किसानों को निर्धारित दर पर, समय पर तथा गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त निगरानी और कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बेमेतरा जिले के ग्राम गाड़ाडीह (तहसील देवकर) में अवैध रूप से भंडारित उर्वरकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 585 बोरी उर्वरक जब्त कर गोदाम को सील कर दिया।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देश तथा कृषि विभाग के उप संचालक मोरध्वज डडसेना के मार्गदर्शन में गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा जिलेभर में उर्वरकों की उपलब्धता, गुणवत्ता और मूल्य नियंत्रण को लेकर नियमित औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी दौरान ग्राम गाड़ाडीह में अवैध खाद भंडारण की सूचना मिलने पर उड़नदस्ता दल ने मौके पर पहुंचकर जांच और छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत लगभग 585 बोरी (29.25 मीट्रिक टन) बायो पोटाश एवं बायो ऑर्गेनिक फास्फेट का अवैध भंडारण पाया गया। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए समस्त उर्वरक सामग्री को जब्त कर संबंधित गोदाम को सील कर दिया।

गुणवत्ता जांच के लिए भेजे जाएंगे नमूने

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए उर्वरकों के नमूने भी संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं, जहां उनकी गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूपता की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रशासन की कड़ी नजर

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिले में लगातार निगरानी अभियान जारी रहेगा। यदि कोई निजी कृषि केंद्र, उर्वरक विक्रेता अथवा सहकारी संस्था निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करते, जमाखोरी करते या अमानक उर्वरकों का व्यापार करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गंभीर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सीधे पुलिस में एफआईआर दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई भी की जाएगी।

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने किसानों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी तत्काल कृषि विभाग या जिला प्रशासन को दें। शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त सूचना पर बिना पूर्व सूचना के त्वरित जांच एवं छापामार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का सशक्त हथियार- डॉ. जीतेन्द्र कुमार

संचालक ने कबीरधाम जिले के बोड़ला विख में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

सामाजिक अंकेक्षण इकाई के संचालक डॉ. जीतेन्द्र कुमार सिंगरौल ने कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हनी के टोला में महात्मा गांधी नरेगा योजना में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्रामीण मजदूरों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर जानकारी ली।

ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए उनका ज्ञानवर्धन किया। डॉ. सिंगरौल ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण मजदूरों के हाथ में एक प्रभावी और सशक्त हथियार है, जिसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है कि योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित कार्यों में सही हुआ है अथवा नहीं। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में मजदूरों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी ग्राम सभाओं को अधिक सशक्त बनाता है तथा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उद्देश्य केवल परिसंपत्तियों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थायी परिसंपत्तियाँ विकसित करना है जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त हो। डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण एवं अन्य जल संरक्षण संबंधी कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ भू-जल स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ. सिंगरौल ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन से जुड़े कार्यों को गंभीरता और ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि यदि आज जल संरक्षण के कार्य प्रभावी ढंग से किए जाएंगे, तो भविष्य की पीढ़ियों को जल संकट जैसी गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि गांवों और टोलों में जाकर मजदूरों से सीधे संवाद करना इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक अंकेक्षण केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों को उनके अधिकारों, योजनाओं की उपयोगिता तथा विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का एक सशक्त माध्यम है। भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के साथ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के जिला प्रभारी दुर्गेश कुमार यादव, ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता विनोद साहू, ग्राम सामाजिक अंकेक्षक संजय चंद्रवंशी, सुलोचनी कश्यप व नीलम पटेल के साथ ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

छात्रावास एवं आश्रम शालाओं में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निजी चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित

छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना, वर्ष 2007 के अंतर्गत कबीरधाम जिले में संचालित छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में निवासरत छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निजी चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण कार्य स्थानीय स्तर पर अनुबंध के आधार पर संपादित किया जाना है। इसके लिए एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. एवं बी.एच.एम.एस. अहर्ता प्राप्त निजी चिकित्सक 25 जून 2026 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना अंतर्गत जिन छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है, उनकी सूची, अनुबंध की शर्तें तथा अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा), कबीरधाम में अवलोकन की जा सकती है।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव के जन्मदिन पर उमड़ा जनसैलाब, डॉ. रमन सिंह ने दिया आशीर्वाद

48वें जन्मदिन पर युवाओं ने किया 48 यूनिट रक्तदान, देर रात तक चलता रहा बधाई का सिलसिला

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव का 48वां जन्मदिन सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। देर रात तक शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम में शामिल होकर मंत्री यादव को स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद दिया।

जन्मदिन समारोह की शुरुआत सुबह चंडी मंदिर और गणेश मंदिर में पूजा-अचर्ना से हुई। इसके बाद विद्युत नगर स्थित निवास और सेवा सदन में बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 11 बजे से सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में शहर के सभी समाज, वर्ग, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने शामिल होकर अपना प्यार बरसाया।

भजन संध्या और छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक प्रस्तुति

कार्यक्रम में कान्हा जी महाराज की टीम ने भजन संध्या की प्रस्तुति दी। देर शाम प्रसिद्ध गायक सुनील सोनी और उनकी टीम ने छत्तीसगढ़ी गीत-संगीत की सांस्कृतिक प्रस्तुति दी।

युवाओं ने किया 48 यूनिट रक्तदान

मंत्री के 48वें जन्मदिन को खास बनाने दुर्ग के युवाओं ने 48 यूनिट रक्तदान किया। यह रक्त अस्पताल को दिया जाएगा ताकि जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क मिल सके। रक्तदान करने वाले युवाओं को संस्था की ओर से निःशुल्क हेलमेट और प्रशस्ति पत्र दिया गया।

ये जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

समारोह में वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन, विधायक ललित चंद्राकर, विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, पूर्व विधायक सांवला राम डाहरे, पूर्व मंत्री रामशीला साहू, पूर्व विधायक डॉ. दयाराम साहू, अपैक्स बैंक से भरत वर्मा, महापौर अलका बाघमार, खादी ग्रामोद्योग अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, इंद्रजीत सिंह, लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी, समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक किरण कौशल, माशिमं सचिव पुष्पा साहू, तेलघानी विकास बोर्ड अध्यक्ष जीतेन्द्र साहू, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौड़, आईजी अभिषेक सांडिल्य, कलेक्टर अभिजीत सिंह, एसपी विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए।

आतिशबाजी कर जताया उत्साह

सुबह से ही विधायक निवास पर शुभचिंतकों की भीड़ रही। किसी ने उपहार दिया तो किसी ने केक काटा। महिलाओं ने मंगल तिलक कर दीर्घायु की कामना की। युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। भिलाई से पहुंची श्रीमति उमरे ने नए ट्राईसिकल की मांग की, जिस पर मंत्री ने जल्द पूरा करने का वादा किया।

नागरिकों ने गमछा भेंट कर सम्मान किया और कहा कि गजेन्द्र यादव अपनी सादगी और अपनेपन के व्यवहार से सबका दिल जीत लेते हैं। अब मंत्री बनकर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य तय कर रहे हैं।

सर्व कल्याण समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने की मंत्री गजेन्द्र यादव से मुलाकात, दी बधाई

भिलाई। शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन गजेन्द्र यादव के जन्मदिवस पर सर्व कल्याण समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर सर्व समाज कल्याण समिति एवं भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी मंत्री गजेन्द्र यादव को जन्मदिवस की मंगलमय बधाई प्रेषित की।

नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा को सर्व कल्याण समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने दी बधाई

नगर पालिक निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा पार्षद भोजराज सिन्हा के जन्मदिन पर सर्व कल्याण समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने उनसे सौजन्य मुलाकात कर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस दौरान इंद्रजीत सिंह छोटू ने भोजराज सिन्हा के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

भिलाई में केनरा बैंक एटीएम में तोड़फोड़, दो युवक को पुलिस ने किया चिन्हांकित

छावनी पुलिस ने की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, एसडीएम कोर्ट में पेश

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नंदनी रोड स्थित बेदी कॉम्प्लेक्स के केनरा बैंक एटीएम के गेट में तोड़फोड़ करने वाले दो युवकों को छावनी पुलिस ने चिन्हांकित कर लिया है। दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर प्रतिबंधात्मक कार्वाई के लिए एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।

13 जून को हुई थी घटना

13 जून को प्रार्थी अशोक कुमार जांगड़े, निवासी प्रगति नगर रिसाली ने थाना छावनी में लिखित आवेदन दिया था। आवेदन में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा केनरा बैंक एटीएम के गेट में तोड़फोड़ की शिकायत की गई थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 388/2026 धारा 324(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पूछताछ में कबूला जुर्म

मुखबिर सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने एटीएम के गेट में तोड़फोड़ करना स्वीकार कर लिया।

आरोपी और कार्रवाई

आरोपियों की पहचान शिवम कुमार (19) और रितिक कुमार सिंह (19), दोनों निवासी युवा अंकुश चौक, छावनी के रूप में हुई है। अपराध जमानतीय होने से दोनों को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगासा तैयार कर एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

शरारतवश की तोड़फोड़

पुलिस के अनुसार घटना का कारण शरारत और असामाजिक गतिविधि के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। प्रकरण में कोई जप्ती नहीं हुई। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा में सहयोग करें। तोड़फोड़ या उपद्रव की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई में थाना छावनी पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

गांजा बेचते आरोपी गिरफ्तार, 4.136 किलो गांजा जब्त

रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरस्वती नगर पुलिस ने एक आरोपी को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4.136 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 5 हजार रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 जून 2026 को थाना सरस्वती नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंडित रविशंकर शुक्ल हेलिपैड की दीवार के पास स्थित झाड़ियों और घुरवा क्षेत्र के समीप एक व्यक्ति गांजा बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप कुमार पटेल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

मानसून की रफ्तार पर लगा ब्रेक : तेलंगाना में 6 दिन से अटका, छग-एमपी में बारिश को एक हफ्ते का इंतजार

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली-रायपुर

देश के बड़े हिस्से में मानसून की सुस्ती से गर्मी का कहर लौट आया है। तेलंगाना के भद्राचलम में पिछले 6 दिनों से अटके मानसून के कारण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश की एंट्री टल गई है। नतीजा, इन राज्यों के कई इलाकों में तापमान फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑगर्नाइजेशन की हाइड्रो मेट्री टीम के सदस्य डॉ. पंकज कुमार के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने में 4 से 5 दिन और मध्य प्रदेश में करीब एक हफ्ता लग सकता है। हालांकि इस हफ्ते के अंत तक बारिश की गतिविधियों में सुधार की उम्मीद है।

कहां पहुंचा मानसून, कहां इंतजार : 15 जून तक मानसून केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में प्रवेश कर चुका है। 16 जून से 5 जुलाई के बीच इसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान पहुंचना है।

64% कम हुई बारिश : मौसम विभाग के मुताबिक 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन हुई सिर्फ 19.2 मिमी। यानी 64% की कमी दर्ज की गई। 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से से मानसूनी बादल गायब दिखे। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में नमी की कमी नहीं है, बल्कि ऊपरी वायुमंडल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सामान्य से ज्यादा दक्षिण खिसकने से मानसूनी हवाएं प्रभावित हो रही हैं।

अगले दो दिन का पूर्वानुमान : 17 जून : बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश संभव। बिहार में 50-70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक में भारी बारिश के आसार। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में गरज-चमक के साथ 40-60 किमी प्रति घंटा की हवा चल सकती है।

क्या है जेट स्ट्रीम? : वायुमंडल की ऊपरी परतों में 8 से 15 किमी की ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। यही हवाएं मानसूनी बादलों और पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करती हैं। इसके दक्षिण खिसकने से मानसून की रफ्तार थम गई है।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100